RNI NO.- CHHHIN/2023/87391

स्वतंत्र छत्तीसगढ़

अंक-04 वर्ष-3 माह-जुलाई 2025 प्रकाशन तिथि- जुलाई 2025 रायपुर से प्रकाशित पृष्ठ-40 मूल्य-11/-

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 2025

विकास और विवाद के बीच गतिशील लोकतंत्र का परिचायक

कृषि संकट और खाद आपूर्ति विवाद

बिजली दरों में वृद्धि पर बहस

नवा रायपुर की ओर एक नया अध्याय

LIC
भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

भारतीय सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम
की संयुक्त विशेष भर्ती योजना

"बीमा सखी" महिला बीमा अभिकर्ता

3 वर्ष तक प्रतिमाह मानदेय

- 1st Year Rs. 7000 P.M.
- 2nd Year Rs. 6000 P.M.
- 3rd Year Rs. 5000 P.M.

साथ ही आकर्षक

अतिरिक्त कमीशन

बीमा सखी के अन्य लाभ

पार्ट टाईम/फूल टाइम कार्य
ग्रुप बीमा, होम लोन इत्यादि

आवश्यक शर्तें : 10 वीं पास उम्र 18 वर्ष से अधिक

एलआईसी महिला विशेष भर्ती

महिला कैरियर एजेंट के रूप में
एलआईसी से जुड़ें

Years	RS
1st	Rs. 7000/-
2nd	Rs. 6000/-
3rd	Rs. 5000/-

B.V.S.Rajkumar
(OVER FOUR DECADES OF EXPERIENCE)
L.I.C.OF INDIA, RAIPUR

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

98266-38002

स्वतंत्र छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ से प्रकाशित एक सम्पूर्ण पत्रिका

प्रधान संपादकः

जी. भूषण राव

समाचार संपादकः

जी.वी.एस. रूक्मणि देवी

उप संपादकः

राखी श्रीवास्तव

सलाहकार संपादकः

रविश बेंजामिन

अशोक तोमर

मार्केटिंग हेडः

शैलेन्द्र दवे

मार्केटिंग प्रतिनिधिः

हरिमोहन तिवारी

आवरण सज्जाः

Infinity

ब्यूरो हेडः

बिलासपुरः विनीत चौहान

जशपुरः आनंद गुप्ता

कोरियाः प्रवीण निशी

बस्तरः सुनील सिंह राठौर

आफिसः

बी-13, बसंत पार्क

अनमोल सुपर मार्केट के पास

महावीर नगर, न्यू पुरेना रायपुर छ.ग.

ईमेलः swatantrachhattisgarh@gmail.com

वेबसाईटः www.swatantrachhattisgarh.com

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक

जी. भूषण राव द्वारा सागर प्रिंटर्स, पुरानी बस्ती रायपुर द्वारा मुद्रित एवं बी-13, बसंत पार्क, अनमोल सुपर मार्केट के पास, महावीर नगर, न्यू पुरेना, रायपुर (छ.ग.) से प्रकाशित

मो.:- 99934-54909

संपादकः जी. भूषण राव

पत्रिका में प्रकाशित लेख, लेखकों के अपने विचार है, किसी भी विवाद की स्थिति में सुनवाई का क्षेत्र रायपुर होगा।

वार्षिक सदस्यता शुल्क सभी

(विशेषांकों सहित प्रस्तावित) 132/-रू.मात्र

Pg 3

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 2025- विकास और विवाद के बीच गतिशील लोकतंत्र का परिचायक

Pg 7

छत्तीसगढ़- हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर

Pg 13

बलौदा की पहाड़ियों पर कंटूर ट्रेंच से जल संरक्षण और हरियाली की दिशा में बड़ा कदम

Pg 15

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से ऐतिहासिक स्वीकृति चावल उपार्जन लक्ष्य में 8 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि

Pg 20

शिव की भक्ति ,
योग की शक्ति ...

सत्ता, सियासत और शराब का
छलकता सच - दोषी कौन ?

राजनीति, जो मूलतः जनसेवा का माध्यम है, अब अनेक अवसरों पर निजी स्वार्थ, सत्ता की लिप्सा और भ्रष्ट गठबंधनों का रंग ओढ़ चुकी है। जब भी कोई घोटाला सामने आता है – विशेषकर शराब जैसे सामाजिक और स्वास्थ्य से जुड़े विषय पर – तो सबसे पहले सवाल उठता है, कौन लाभान्वित हुआ? शराब घोटालों में अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक दलों के नेताओं, उनके परिजनों या करीबी व्यापारिक गठजोड़ों को सीधे या परोक्ष लाभ होता है। सत्तारूढ़ दल आरोपों से बचाव करता है, विपक्ष उन पर हमला बोलता है, और अंततः जनता के प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। राजनीति की यह चुप्पी असल में मिलीभगत की गूंज होती है। सरकारों का यह दायित्व है कि वे समाज की संरचना को न्यायसंगत और स्वास्थ्यकारी बनाएं। लेकिन जब सरकार ही शराब नीति के नाम पर राजस्व के लालच में डूब जाए, तब प्रश्न उठता है कि नीति बनती है या बिकती है? हाल के वर्षों में कई राज्य सरकारों ने शराब नीति में छूट दी, नए लाइसेंस जारी किए और निजी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों को मोड़ा। कई बार यह भी देखा गया कि शराब कारोबार से जुड़ी कंपनियों को राजनीतिक चंदा देने के एवज में नीतियों में परिवर्तन किए गए। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारें शराब को राजस्व का ज़रिया तो मानती हैं, लेकिन इससे उत्पन्न सामाजिक क्षति को नजरअंदाज कर देती हैं।

भारत के अनेक राज्यों में शराब घोटाले सामने आए हैं — चाहे वह दिल्ली का कथित आबकारी घोटाला हो, मध्य प्रदेश या बिहार में अवैध शराब के चलते हुई मौतें हों, या छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में आबकारी विभाग की कथित मिलीभगत। इन सभी मामलों में एक बात समान है – जनता के स्वास्थ्य और राज्य के संसाधनों से खिलवाड़। शराब घोटालों की छानबीन या तो राजनैतिक बदले की भावना से शुरू होती है या फिर दबाव में रुक जाती है। ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय एजेंसियों की जांच भी जब पक्षपातपूर्ण प्रतीत होती है, तब आमजन का भरोसा लोकतंत्र से डगमगाने लगता है।

राजनीति, सरकार और शराब घोटाला — इस त्रिकोण में कहीं न कहीं एक आम नागरिक फंसा हुआ है। चुनावों में वोट देकर सरकार चुनी जाती है, नीति बनाकर वही सरकार शराब को खुलेआम बढ़ावा देती है, और जब घोटाले होते हैं तो जांच के नाम पर केवल सत्ता संघर्ष होता है। अब समय आ गया है कि जनता जागरूक हो, शराब नीति पर प्रश्न पूछे, और उन नेताओं से जवाब मांगे जो नैतिकता की बात तो करते हैं, लेकिन व्यवहार में अवसरवाद दिखाते हैं। लोकतंत्र की सच्ची ताकत तभी प्रकट होगी, जब शराब और सत्ता का यह नशा जनता के विवेक से टूटेगा।

आपका अपना
भूषण राव

छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 2025

विकास और विवाद के बीच गतिशील लोकतंत्र का परिचायक

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 2025 कई मायनों में ऐतिहासिक और घटनाप्रधान रहा। दिनांक 14 जुलाई से 18 जुलाई तक आयोजित यह सत्र सिर्फ विधायी कार्यवाही तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह प्रदेश के वर्तमान प्रशासनिक मिजाज, जन सरोकारों, तथा विपक्ष के तेवरों को भी खुलकर सामने लाने वाला एक सशक्त मंच सिद्ध हुआ। यह सत्र वर्तमान विधानसभा भवन में अंतिम था, क्योंकि अगला सत्र नवा रायपुर स्थित नवनिर्मित भवन में संपन्न होगा। कुल 5 कार्यदिवसों में 6 बैठकें हुईं, जिनमें 13 महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इसके साथ ही विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तेज़ बहस, निलंबन, स्थगन प्रस्तावों और जनमुद्दों पर गहन चर्चा ने इस सत्र को संसदीय इतिहास में एक जीवंत अध्याय बना दिया।

विधायी कार्य- गति और घनत्व का संतुलन

इस सत्र में 13 प्रमुख विधेयकों को पारित किया गया। ये विधेयक मुख्यतः कृषि, पेंशन, धार्मिक स्वतंत्रता, महिला-बाल कल्याण, प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित थे। इनमें उल्लेखनीय विधेयक निम्नलिखित हैं-

- छत्तीसगढ़ विशेष धार्मिक स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025- राज्य में जबरन या छलपूर्वक धर्मांतरण पर कठोर प्रावधान।
- पेंशन फंड नियमन विधेयक- राज्य कर्मियों के पेंशन फंड के पारदर्शी प्रबंधन हेतु प्रावधान।
- राजस्व विशेष सेवा संवर्ग (SCR) विधेयक- प्रशासनिक दक्षता हेतु राजस्व अधिकारियों का पृथक कैडर।
- राज्य एंबुलेंस सेवा नियमन विधेयक- स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में एंबुलेंस सेवा का केंद्रीकृत प्रबंधन।
- महिला व बाल विकास हेतु तैयार भोजन वितरण नीति- स्कूलों और आंगनबाड़ियों में तैयार पोषणयुक्त भोजन का कानूनी ढांचा।

सरकार ने इस त्वरित विधायी कार्यवाही को जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता बताया, वहीं विपक्ष ने इसे बहस से वंचित, एकतरफा निर्णय कहकर आक्षेप लगाए।

- विपक्ष का मुखर रुख- जनता की आवाज़ या राजनीतिक रणनीति?

कृषि संकट और खाद आपूर्ति विवाद-

मानसून सत्र का सबसे बड़ा मुद्दा छ्रक्क खाद की कमी रहा। विपक्ष ने दावा किया कि किसानों को खाद और बीज समय पर नहीं मिल रहे, जिससे खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो रही है।

- 14 जुलाई को इस विषय पर अस्थगन प्रस्ताव लाया गया, जिसके कारण सदन में भारी हंगामा हुआ और 23 कांग्रेस विधायक निलंबित किए गए।

- कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि 3.10 लाख टन की मांग के विरुद्ध सिर्फ 1.1 लाख टन DAP उपलब्ध हुआ है।
- विकल्प के रूप में नैनो-DAP और पोटाश के उपयोग को बढ़ावा देने की बात कही गई।

17 जुलाई को फिर से इस मुद्दे पर सदन में गतिरोध उत्पन्न हुआ। इस बार 30 विधायकों को एक दिन के लिए निलंबित किया गया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि खाद वितरण में निजी विक्रेताओं को अनुचित लाभ दिया गया है।

बिजली दरों में वृद्धि पर बहस

सत्र के तीसरे दिन बिजली दरों में 1.89प्रतिशत वृद्धि को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा।

- कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि यह निर्णय 60 लाख उपभोक्ताओं के लिए आर्थिक बोझ है।
- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सदन में स्पष्ट किया कि दरें देश के न्यूनतम स्तर पर हैं और सरकार ने किसानों, उद्योगों और गरीबों के लिए सब्सिडी व राहत योजना भी लागू की है।

विपक्ष का तर्क था कि सरकार मूलभूत सेवाओं का निजीकरण कर रही है, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है।

नवा रायपुर की ओर- एक नया अध्याय

इस सत्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी रही कि यह पुराने विधानसभा भवन में आयोजित अंतिम सत्र था। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अगला सत्र नवा रायपुर के अत्याधुनिक भवन में संपन्न होगा, जो डिजिटल सुविधा, उच्च तकनीकी सुरक्षा और बेहतर कार्यप्रणाली से युक्त होगा।

नेता प्रतिपक्ष ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, भवन बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती। असली परिवर्तन प्रशासन के व्यवहार और संवेदनशीलता में होना चाहिए।

लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण

मानसून सत्र 2025 ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि छत्तीसगढ़ की विधानसभा वास्तविक जनसरोकारों का मंच है।

जहां एक ओर सरकार ने विधेयकों के माध्यम से शासन के विविध क्षेत्रों में सुधार की दिशा में स्पष्ट दृष्टि दिखाई, वहीं विपक्ष ने भी बिना रुके जनता के मुद्दों को आवाज़ देने का काम किया।

इस सत्र में—

- जनसमस्याओं पर केंद्रित बहसें हुईं।
- विपक्ष की आक्रामक शैली और निलंबन लोकतांत्रिक असहमति की मिसाल बने।
- 13 विधेयकों का त्वरित पारित होना विधायी सक्रियता का प्रतीक रहा।
- और नवा रायपुर के नए भवन की तैयारी ने भविष्य की ओर संकेत दिया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 2025 एक ऐसा आईना रहा जिसमें विकास की आकांक्षा और लोकतंत्र की आवाज़ दोनों झलकती हैं।

तुमनार आयुष्मान आरोग्य मंदिर को NQAS प्रमाण पत्र

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में स्वास्थ्य सेवाओं की ऐतिहासिक सफलता

छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल और नक्सल प्रभावित राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार लाना हमेशा एक चुनौती रहा है। लेकिन बीजापुर जिले के तुमनार गांव में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने इस चुनौती को अवसर में बदलते हुए एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में इस केंद्र को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (National Quality Assurance Standards - NQAS) प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। इस आरोग्य मंदिर ने 96.4 प्रतिशत अंकों के साथ यह प्रमाणन प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

तुमनार आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी आयुष्मान भारत योजना के तहत की गई थी। यह योजना देश के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी। बीजापुर जैसे दुर्गम और नक्सल प्रभावित इलाके में इस योजना के तहत इस केंद्र की स्थापना एक सराहनीय और साहसिक कदम माना गया। स्थानीय लोगों को न केवल बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं, बल्कि इस केंद्र ने स्वास्थ्य देखभाल के व्यापक आयामों जैसे रोकथाम, प्रोत्साहन, उपचार, पुनर्वास और उपशामक देखभाल में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। यह केंद्र अब पूरे राज्य के लिए एक मॉडल हेल्थ सेंटर बनकर उभरा है।

एनक्यूएएस प्रमाणन की प्रक्रिया और मानक

राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) भारत सरकार का एक प्रमुख गुणवत्ता मूल्यांकन तंत्र है, जिसके तहत देश भर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों का मूल्यांकन किया जाता है। इसके तहत स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे, रिकॉर्ड प्रबंधन, रोगी देखभाल, स्वच्छता, कर्मचारियों के व्यवहार और सेवा की निरंतरता जैसे कई मानकों पर केंद्रों का मूल्यांकन किया जाता है।

तुमनार आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने इन सभी मानकों पर बेहद उच्च प्रदर्शन करते हुए कुल 96.4 प्रतिशत अंक हासिल किए। इस आंकड़े ने न केवल छत्तीसगढ़, बल्कि देशभर में इस केंद्र की पहचान मजबूत की है।

क्या है तुमनार आरोग्य मंदिर की विशेषता?

तुमनार आरोग्य मंदिर की सफलता के पीछे कई विशेषताएं हैं-

- समर्पित और प्रशिक्षित स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हर परिस्थिति में मरीजों की सेवा में तत्पर रहते हैं।
- उन्नत बुनियादी ढांचा, जिसमें प्रसव कक्ष, लैब सेवाएं, टेलीमेडिसिन, इमरजेंसी सेवा, और पर्याप्त दवा भंडारण शामिल है।
- डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली जिससे रोगियों की चिकित्सा जानकारी का सुव्यवस्थित संकलन होता है।
- स्वच्छता और संक्रमण नियंत्रण की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास, जिसके चलते रोगियों और कर्मचारियों को सुरक्षित वातावरण मिलता है।
- सामुदायिक सहभागिता, जिसके अंतर्गत ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाता है और स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन होता है।
- छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस

उपलब्धि को बीजापुर जिले के लिए गर्व की बात बताया। उन्होंने कहा-यह उपलब्धि हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के समर्पण और सहयोग के प्रयासों का परिणाम है। हमारी सरकार का मकसद सूबे के प्रत्येक नागरिक को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह उपलब्धि उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।÷

आदिवासी समुदाय को स्वास्थ्य लाभ

- बीजापुर जिले की बड़ी आबादी आदिवासी समुदाय की है, जो वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं की उपेक्षा झेल रही थी। इस आरोग्य मंदिर के कारण अब क्षेत्रीय जनसंख्या को अनेक प्रकार की सेवाएं जैसे-
- गैर-संचारी रोगों (डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर आदि) का समय रहते निदान और उपचार
- मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, जिनकी ग्रामीण क्षेत्रों में भारी कमी रहती है नेत्र रोगों का इलाज और परामर्श
- वृद्धजन देखभाल, जिनके लिए विशिष्ट चिकित्सा सुविधाएं अब सुलभ हैं
- आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं, सर्पदंश जैसी स्थितियों में त्वरित इलाज संभव हुआ है।

दूरदराज क्षेत्रों के लिए बना उदाहरण

तुमनार आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि नीति, नियोजन और निष्पादन में प्रतिबद्धता हो, तो किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सकती है ङ्क चाहे वह कितना भी दुर्गम या संवेदनशील क्यों न हो। इसके सफल संचालन से प्रेरणा लेकर सरकार ने अन्य दूरदराज जिलों में भी इसी प्रकार के मॉडल केंद्रों की स्थापना और मौजूदा केंद्रों के उन्नयन की योजना बनाई है।

भविष्य की योजनाएं

राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग की योजना है कि-

- अन्य हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को भी एनक्यूएएस मानकों पर प्रशिक्षित और उन्नत किया जाए।
- टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार किया जाए ताकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं हर गांव तक पहुंच सकें।
- आदिवासी भाषा में स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा दी जाए ताकि संप्रेषण अधिक प्रभावी हो सके।
- मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त किया जाए।

तुमनार आयुष्मान आरोग्य मंदिर की यह सफलता छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की एक नई कहानी लिख रही है। यह न केवल एक प्रमाणपत्र की उपलब्धि है, बल्कि यह राज्य की उस दूरदर्शिता और प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए कार्यरत है।

बीजापुर जैसे क्षेत्र में यह उपलब्धि एक प्रेरणास्त्रोत बन चुकी है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में भी इसी तरह की सफल कहानियां सामने आएंगी।

आंगनबाड़ियों में दिख रहा बदलाव, बच्चों को मिल रहा खेल-खेल में ज्ञान, संस्कार और पोषण

छत्तीसगढ़ की आंगनबाड़ियाँ अब बच्चों के पोषण के साथ-साथ शिक्षा, संस्कार और स्वास्थ्य के नए केंद्र बन रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा है कि राज्य सरकार का लक्ष्य आंगनबाड़ियों को नवाचारयुक्त बाल विकास केंद्र के रूप में स्थापित करना है, जहां बचपन संवरता है और भविष्य मजबूत होता है। राज्य के अधिकांश आंगनबाड़ी केंद्र अब पारंपरिक स्वरूप से निकलकर प्री-स्कूल प्ले लर्निंग स्पेस के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। यहां बच्चों को कहानियों, चित्रों, लोकगीतों और गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता, भाषा विकास और नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है। बेमेतरा जिले का बोइरकछरा आंगनबाड़ी केंद्र राज्य में एक उत्कृष्ट मॉडल बनकर उभरा है। यहां बच्चों का शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और रचनात्मक विकास सुनियोजित तरीके से हो रहा है। दीवारों पर शैक्षणिक चित्रों और बालगीतों की प्रस्तुति, मोर जन्म दिन कैलेंडर और बच्चों के लिए तैयार किए गए ÷कैरी बैग÷ जैसे नवाचार बच्चों में आत्मविश्वास और सामाजिकता का संचार कर रहे हैं।

आंगनबाड़ी केंद्रों में किशोरी बालिकाओं को माहवारी स्वच्छता, आत्मरक्षा, पोषण और आत्मनिर्भरता के गुर सिखाए जा रहे हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं को स्तनपान, नवजात देखभाल और संतुलित आहार से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जा रही हैं। पूरक पोषण आहार योजना के तहत बच्चों और महिलाओं को पौष्टिक भोजन जैसे हरे साग, मुनगा भाजी पाउडर, फल, रोटी-सब्जी और दाल-भात प्रदान किया जा रहा है। बेमेतरा की जिला कार्यक्रम अधिकारी ने जानकारी दी कि बोइरकछरा केंद्र में महतारी वंदन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना, मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और महिला सक्षम कोष सहित सभी प्रमुख योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस सफलता के पीछे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती प्यारी ध्रुव और सहायिका की अहम भूमिका रही है, जिनकी निष्ठा और रचनात्मक सोच इस केंद्र को प्रेरणास्त्रोत बनाती है। मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को इसी तरह शिक्षा, पोषण और संस्कार के समेकित केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि हर बच्चा सशक्त, शिक्षित और स्वस्थ बन सके।÷ छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों से आंगनबाड़ी केंद्र अब बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की नींव बन रहे हैं कृ जहां पोषण के साथ संस्कार और ज्ञान का भी समुचित समावेश हो रहा है।

छत्तीसगढ़- हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में अग्रसर

छत्तीसगढ़, जो अब तक अपने समृद्ध वन-संसाधनों और जैव विविधता के लिए जाना जाता था, अब भारत में हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेज़ी से अग्रसर हो रहा है। यह बदलाव राज्य सरकार की दूरदृष्टि, रणनीतिक नीतियों और केंद्र सरकार के 'वोकल फॉर लोकल' और 'आत्मनिर्भर भारत' जैसे अभियानों के सहयोग से संभव हो रहा है। इस दिशा में एक बड़ा कदम दुर्ग जिले के जामगांव (एम) में अत्याधुनिक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई की स्थापना के रूप में सामने आया है।

जामगांव (एम) में स्थापित यह अत्याधुनिक प्रसंस्करण इकाई 27.87 एकड़ भूमि में फैली हुई है और इसमें फार्मास्युटिकल ग्रेड की आधुनिक मशीनों की सहायता से हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों का उत्पादन किया जा रहा है। यह इकाई छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा निर्मित की गई है और इसका संचालन पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल के अंतर्गत किया जा रहा है।

यहां आयुर्वेदिक औषधियों के विभिन्न रूपों — जैसे चूर्ण, सिरप, तेल, अवलेह और टैबलेट — का निर्माण, प्रसंस्करण और पैकेजिंग आधुनिक तकनीकों से किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जंगलों से प्राप्त लघु वनोपजों को स्थानीय स्तर पर ही प्रोसेस करके उनकी गुणवत्ता और मूल्य में वृद्धि करना है।

इस परियोजना के माध्यम से 'फारेस्ट टू फार्मेसी' मॉडल की प्रभावशाली शुरुआत हुई है, जिसका मतलब है ङ्क जंगलों से सीधे औषधीय और वेलनेस उत्पादों का उत्पादन। इससे न सिर्फ पारंपरिक ज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होगा, बल्कि इससे स्थानीय जनजातीय समुदायों को आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर भी मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में इस परियोजना को विशेष प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने हाल ही में इस इकाई का लोकार्पण करते हुए इसे राज्य की नई औद्योगिक नीति का हिस्सा बताया है, जिसमें वनोपज प्रसंस्करण इकाइयों को थ्रस्ट सेक्टर में शामिल किया गया है।

इस प्रसंस्करण इकाई में कुल 36.47 करोड़ रुपये की लागत से कई महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गई हैं, जिनमें-

- क्वॉरेंटाइन बिल्डिंग
- प्री-प्रोसेसिंग यूनिट
- मटेरियल स्टोरेज बिल्डिंग
- मुख्य उत्पादन संयंत्र (मेन प्लांट बिल्डिंग)

इसके अतिरिक्त, एक अलग हर्बल एक्सट्रैक्शन यूनिट भी बनाई गई है जो 6.04 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई है और इसकी लागत 23.24 करोड़ रुपये है। इस यूनिट में गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा, सफेद मूसली, गुड़मार, शतावरी, जंगली हल्दी, बहेड़ा जैसे औषधीय पौधों से अर्क निकालने की आधुनिक प्रणाली विकसित की गई है।

यह अर्क आयुर्वेदिक औषधियों, हर्बल उत्पादों और वेलनेस उत्पादों के निर्माण में काम में लाए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय हर्बल उत्पाद बाज़ार में अपनी एक विशिष्ट पहचान

स्थापित करने में मदद मिलेगी।

इस केंद्र से 2000 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। इनमें आदिवासी और वनवासी समुदायों, विशेषकर महिलाओं, को लघु वनोपजों के संग्रहण, प्राथमिक प्रसंस्करण और पैकेजिंग में शामिल किया जाएगा। इससे उनकी आय में वृद्धि, स्थानीय अर्थव्यवस्था में सुधार और जीवन-स्तर में बदलाव आएगा।

छत्तीसगढ़ की लगभग 44 प्रतिशत भूमि वनों से आच्छादित है और यहां 150 से अधिक प्रकार की लघु वनोपज उपलब्ध हैं। इनमें साल बीज, तेंदूपत्ता, महुआ, हर्रा, बहेरा, गिलोय, अश्वगंधा जैसी कई औषधीय वनस्पतियाँ शामिल हैं। पहले ये कच्चे रूप में ही बिकती थीं और इनका पूरा लाभ राज्य को नहीं मिल पाता था। लेकिन अब इनका स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन करके न केवल राजस्व में वृद्धि की जाएगी, बल्कि राज्य के युवाओं और उद्यमियों को भी स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे।

आज विश्वभर में हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। कोविड-19 महामारी के बाद लोगों में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उत्पादों की रुचि बढ़ी है, जिससे हर्बल और प्राकृतिक औषधियों की अहमियत वैश्विक स्तर पर भी बढ़ गई है। भारत की पारंपरिक आयुर्वेदिक पद्धति अब दुनिया भर में सम्मान पा रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की यह पहल देश को हर्बल उत्पादों का एक मजबूत निर्यातक भी बना सकती है।

छत्तीसगढ़ की यह नई पहल न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि जनजातीय समुदायों को सशक्त , प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित और भारत को हर्बल उत्पादों में वैश्विक नेतृत्व दिलाने की दिशा में भी एक बड़ा कदम साबित होगी। जामगांव की यह केन्द्रीय प्रसंस्करण इकाई राज्य को वन आधारित अर्थव्यवस्था के मॉडल में अग्रणी बनाने की ओर एक सशक्त प्रयास है।

यह मॉडल भविष्य में अन्य राज्यों और देशों के लिए भी एक प्रेरणास्रोत बन सकता है। छत्तीसगढ़ अब केवल वनों का राज्य नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का हर्बल केंद्र बनकर उभर रहा है।

किसानो के हित में निरंतर कार्य कर रही है राज्य सरकार- रामविचार नेताम

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम आज बलरामपुर जिले के ग्राम जाबर में आयोजित किसान सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान 664 लाख 43 हजार रूपए लागत की 31 कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया। इसमें राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड अन्तर्गत विकासखंड बलरामपुर के ग्राम पंचायतों में सी.सी. रोड के 28 एवं पुल-पुलिया निर्माण के 03 इस तरह कुल 31 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। जिसमें 21 कार्यों का भूमि पूजन जिसकी लागत 408.72 लाख रूपए और 10 कार्यों का लोकार्पण जिसकी लागत 255.71 लाख रूपए शामिल है। उन्होंने इस मौके पर 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत आम का पौधारोपण किया। उन्होंने इस अवसर पर विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री का वितरण भी किया।

कार्यक्रम में मंत्री श्री नेताम के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र के 8 किसान को सम्मानित किया गया। कृषि विभाग से 20 किसानो को रामतिल, उद्यान विभाग से 67 किसानों को पौध वितरण मत्स्य विभाग के द्वारा 01 किसान को कोल्ड बॉक्स, वन विभाग अंतर्गत 10 महिलाओं को चरण पादुका का वितरण किया गया। साथ ही स्वेछानुदान राशि के चेक का वितरण भी किया। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक खेती एवं फसल प्रबंधन पुस्तक का विमोचन भी किया।

कृषि मंत्री श्री नेताम ने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसान हितैषी सरकार है। हमारी सरकार किसानों के हित में कार्य करने व उन्हें लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सभी वर्गों का निरंतर विकास हो रहा है।

उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसे महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत है। प्रतिवर्ष धान की खरीदी के समर्थन मूल्य में निरंतर वृद्धि की जा रही है, जिससे किसानों को उनकी उपज का समुचित मूल्य मिल रहा है जिससे क्षेत्र में भी किसान बहुतायत में धान की फसल ले रहे है। उन्होंने धान के स्थान पर अन्य फसल जैसे मोटा अनाज, दलहन, तिलहन जैसे फसलों लेने प्रेरित किया जिससे कृषि विविधीकरण को बढ़ावा मिल सके। साथ ही उन्होंने डीएपी के वैकल्पिक का उपयोग करने की बात कही। उन्होंने कहा कि तेंदूपता संग्राहक को डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में राशि का अन्तरण किया जा रहा है। इस डिजिटल क्रांति के माध्यम से देश-प्रदेश में बदलाव आया है। डिजिटल क्रांति के माध्यम से शासन की योजनाएं पारदर्शी ढंग से अंतिम व्यक्ति तक पहुँच रही हैं।

घुड़टांगर से ग्रीस तक

अनिमेष कुजूर की दौड़ देश के गौरव तक

छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव घुड़टांगर की कच्ची पगडंडियों से निकलकर ग्रीस के अंतरराष्ट्रीय ट्रैक तक का सफर... यह कहानी है भारत के एक ऐसे होनहार धावक अनिमेष कुजूर की, जिन्होंने न केवल देश के लिए नया कीर्तिमान स्थापित किया, बल्कि हर युवा के लिए प्रेरणा बनकर उभरे।

नंगे पांव की शुरुआत, स्पाइक शूज़ तक की यात्रा

अनिमेष की दौड़ खेतों की मेड़ों से शुरू हुई। कभी बिना जूतों के दौड़ने वाला यह लड़का आज देश की सबसे तेज़ 100 मीटर दौड़ का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। 5 जुलाई 2025 को ग्रीस के वारी शहर में आयोजित ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट मीट में अनिमेष ने 100 मीटर की दौड़ 10.18 सेकंड में पूरी कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। इस प्रतियोगिता में अनिमेष भले ही तीसरे स्थान पर रहे, परंतु उन्होंने इतिहास रच दिया।

परिवार और प्रारंभिक जीवन

अनिमेष कुजूर का जन्म जशपुर जिले के कुनकुरी विकासखंड के घुड़टांगर गांव में हुआ। उनके माता-पिता छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी के पद पर पदस्थ हैं और वर्तमान में बलौदा बाजार में कार्यरत हैं। अनिमेष की प्रारंभिक शिक्षा महासमुंद जिले के वेडनर मिशन स्कूल में हुई। इसके बाद उनका परिवार कांकेर आ गया जहां उन्होंने सेंट माइकल स्कूल में पढ़ाई की। उनके जीवन का बड़ा मोड़ तब आया जब छठवीं कक्षा में उनका चयन सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए हुआ। वहीं से उन्होंने अनुशासन और मेहनत की राह पकड़ी।

दबाव, संघर्ष और स्वाभिमान

कोविड-19 के समय जब सब कुछ बंद हो गया था, तब सैनिक स्कूल में रहकर अनिमेष ने खुद को प्रशिक्षण देना जारी रखा। दिलचस्प बात यह रही कि उन्होंने दौड़ने की बात अपने माता-पिता से छुपाए रखी। उनके पिता अमृत कुजूर बताते हैं, जब उसने पहली बार बताया कि वो दौड़ रहा है, तो हमें खुशी तो हुई लेकिन अंदाजा नहीं था कि यही उसका जुनून बन जाएगा।

पांच स्पर्धाएं, पांच गोल्ड

कांकेर जिले में आयोजित युवा एवं खेल विभाग की एक प्रतियोगिता में अनिमेष ने 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, और हाई जंप–इन सभी में स्वर्ण पदक जीते। इस प्रदर्शन ने उन्हें राज्य स्तरीय पहचान दिलाई और रायपुर वेस्ट ज़ोन एथलेटिक्स मीट के लिए चयनित किया गया, जहाँ उन्होंने 100 और 200 मीटर में गोल्ड मेडल जीतकर गुवाहाटी में आयोजित नेशनल अंडर-18 प्रतियोगिता में स्थान पक्का किया।

अनिमेष कुजूर का सफर यह बताता है कि संसाधनों की कमी कभी भी संघर्षशील संकल्प के आगे टिक नहीं पाती। उनके जीवन में जो अनुशासन सैनिक स्कूल से आया, और जो मेहनत उन्होंने खेतों और मिट्टी की पगडंडियों पर की, उसी ने उन्हें आज देश का स्प्रिंट स्टार बना दिया है।

निष्कर्ष-एक नाम, जो दौड़ रहा है इतिहास की ओर

अनिमेष कुजूर की कहानी उस भारत की कहानी है, जो छोटे गांवों से निकलकर वैश्विक मंच पर अपना झंडा गाड़ता है। उनके पदचिह्नों पर चलने वाले कई युवाओं के लिए यह सफर सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि एक मिशन है।

उनकी दौड़ सिर्फ ट्रैक पर नहीं है–वह दौड़ है संघर्ष से सफलता तक, सपनों से सच्चाई तक।

विशेष बिंदु-

- 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड- 10.18 सेकंड
- 200 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड- 20.32 सेकंड
- शिक्षा- सैनिक स्कूल अंबिकापुर
- मूल निवासी- घुइटांगर, जशपुर (छ.ग.)
- माता-पिता- दोनों डीएसपी, छत्तीसगढ़ पुलिस
- प्रेरणादायक पहलू- अनुशासन, आत्मनिर्भरता, ग्रामीण पृष्ठभूमि से विश्व मंच तक की यात्रा

अनिमेष को स्वतंत्र छत्तीसगढ़ परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनकी दौड़ अनगिनत युवाओं को आगे बढ़ने की राह दिखाएगी।

स्पाइक शूज़ की पहली दौड़

गुवाहाटी में अंडर-18 नेशनल चैंपियनशिप के समय तक अनिमेष ने कभी स्पाइक शूज़ नहीं पहने थे। पहली बार पिता द्वारा दिलाए गए प्रोफेशनल रनिंग शूज़ पहनकर जब वह ट्रैक पर दौड़े, तब भी उन्होंने 100 और 200 मीटर दोनों में चौथा स्थान हासिल किया। यहीं से उनकी राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत हुई।

दूसरा कीर्तिमान- एशियन चैंपियनशिप

ग्रीस से पहले भी अनिमेष ने अपने नाम राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज कराया था। दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में उन्होंने 200 मीटर दौड़ को मात्र 20.32 सेकंड में पूरा कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था। यह उनके प्रदर्शन का एक और ऊंचा मुकाम था।

सम्मान और प्रतिक्रियाएं

अनिमेष की ऐतिहासिक उपलब्धियों पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा,

यह क्षण हम सभी के लिए गर्व का है। अनिमेष की सफलता हर युवा को प्रेरणा देगी।

डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा,

आप भारत का मान विश्व मंच पर बढ़ाते रहें, बधाई और शुभकामनाएं।

वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने लिखा,

आपकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि जशपुर जैसे आदिवासी जिले में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है।

घुइटांगर की उम्मीद- भारत की शान

प्रधानमंत्री मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान

वैश्विक नेतृत्व की नई ऊँचाइयाँ.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो द्वारा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो (ORTT) से सम्मानित किया जाना केवल भारत के लिए गौरव की बात नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर उभरते भारत की नई पहचान का प्रतीक है। यह सम्मान न सिर्फ मोदी के व्यक्तिगत कूटनीतिक कौशल और नेतृत्व क्षमता की पुष्टि करता है, बल्कि भारत के 140 करोड़ नागरिकों के परिश्रम, संकल्प और वैश्विक मंच पर उनकी सक्रिय भागीदारी की भी सराहना है।

यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 25वां अंतरराष्ट्रीय नागरिक सम्मान है, जो दर्शाता है कि भारत की विदेश नीति अब केवल औपचारिकताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि वह व्यावहारिक सहयोग, साझेदारी और वैश्विक हितों की दिशा में ठोस कार्यों पर केंद्रित है। त्रिनिदाद और टोबैगो जैसे कैरेबियाई राष्ट्र से यह सम्मान मिलना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह उन क्षेत्रों में भी भारत की उपस्थिति और प्रभाव को स्थापित करता है, जो पारंपरिक रूप से पश्चिमी या एशियाई भू-राजनीतिक समीकरणों से बाहर माने जाते थे।

प्रधानमंत्री की यह पहली आधिकारिक यात्रा और 1999 के बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली त्रिनिदाद-टोबैगो यात्रा है। यह यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को नई ऊर्जा देने का काम करेगी। सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाकर यह साझेदारी वैश्विक दक्षिण की एक नई आवाज बन सकती है। डिजिटल वित्त, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं और आईटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए जो रणनीतिक रूपरेखा तैयार की जा रही है, वह दोनों देशों के लिए दीर्घकालिक लाभदायक साबित हो सकती है।

त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों की एक मजबूत उपस्थिति है, जो वर्षों से वहां की संस्कृति, राजनीति और अर्थव्यवस्था में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत, पारंपरिक संगीत, नृत्य और भारतीय मूल के लोगों की भागीदारी इस सांस्कृतिक सेतु को और प्रगाढ़ बनाते हैं। यह केवल राजनीतिक दौरा नहीं, बल्कि भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय के बीच भावनात्मक एकता को दर्शाने का अवसर भी है।

त्रिनिदाद और टोबैगो की यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी के पांच देशों के बहुपक्षीय दौरे का हिस्सा है, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया जैसे रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण देश भी शामिल हैं। विशेष रूप से ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनकी भागीदारी से भारत को वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक नीतियों में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिलेगा। यह यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि भारत के लिए वैश्विक नीतियों में निर्णायक भूमिका निभाने की ओर एक ठोस कदम है।

प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा और मिले हुए सम्मान भारत की उस आकांक्षा को भी दर्शाते हैं जिसमें वह न केवल वैश्विक पटल पर आर्थिक शक्ति बनना चाहता है, बल्कि नैतिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक नेतृत्वकर्ता की भूमिका भी निभाना चाहता है। जब अफ्रीका से लेकर कैरेबियन तक भारत के नेतृत्व को सराहा जाता है, तो यह साफ हो जाता है कि भारत की विदेश नीति बहुपक्षीय, समावेशी और वैश्विक साझेदारी की नींव पर खड़ी हो रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो' से नवाजे जाने से भारत को अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो नई प्रतिष्ठा मिली है, वह केवल एक सम्मान नहीं बल्कि भारत की विदेश नीति, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक सहभागिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह सम्मान आने वाले वर्षों में भारत की सॉफ्ट पावर, तकनीकी साझेदारी और वैश्विक संवाद में निर्णायक भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने वाला सिद्ध होगा। अब भारत केवल वैश्विक मंच का भागीदार नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता बनने की दिशा में अग्रसर है।

नक्सलगढ़ से सफलता की उड़ान- रत्ना और संतोष बनेंगे गांव के पहले डॉक्टर, दंतेवाड़ा के बच्चों ने रचा इतिहास

छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से एक प्रेरणादायक खबर आई है, जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश का दिल जीत लिया है। कभी नक्सल हिंसा से जूझता रहा यह इलाका अब शिक्षा की नई अलख जगा रहा है। इसी जिले के नक्सल प्रभावित गांवों से ताल्लुक रखने वाले चार होनहार बच्चों ने नीट परीक्षा पास कर इतिहास रच दिया है। इनमें खास तौर पर दो नाम–रत्ना रामू और संतोष पोडियम–आज मिसाल बनकर उभरे हैं, क्योंकि ये अपने-अपने गांवों के पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं।

रत्ना रामू, दंतेवाड़ा जिले के धूरली गांव की रहने वाली हैं। उनके माता-पिता मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करते हैं। बचपन से ही रत्ना ने डॉक्टर बनने का सपना देखा था और अब जब उन्होंने NEET 2025 में 334 अंक हासिल किए हैं, तो उनका सपना साकार होता नजर आ रहा है। रत्ना का कहना है, ÷मैंने गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को करीब से देखा है। जब कोई बीमार होता है, तो शहर तक पहुंचना बहुत कठिन होता है। मैं चाहती हूं कि गांव में ही रहकर लोगों की सेवा करूं। रत्ना की सफलता में उनकी बड़ी बहन रुमा मरकाम का भी बड़ा योगदान है, जो खुद पढ़ाई पूरी करने के बाद रत्ना की पढ़ाई में मदद करती थीं। परिवार की सीमित आर्थिक स्थिति के बावजूद रत्ना ने हार नहीं मानी और आज वो अपने गांव की पहली डॉक्टर बनने जा रही हैं। चिकपाल गांव के रहने वाले संतोष पोडियम की कहानी भी बेहद मार्मिक और प्रेरणादायक है। पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया और मां ने खेती करके उन्हें पाला-पोसा। संतोष ने नीट में 336 अंक हासिल किए हैं और वह अपने गांव के पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं।

संतोष कहते हैं, हमारे गांव में डॉक्टर तो दूर की बात, स्कूल और अस्पताल भी नहीं थे। मां ने मुश्किलों के बावजूद मुझे पढ़ाया, मैं डॉक्टर बनकर यहीं प्रैक्टिस करूंगा ताकि गांव के लोगों को इलाज के लिए शहर न भागना पड़े।

रत्ना और संतोष की सफलता का बड़ा श्रेय दंतेवाड़ा जिले की आवासीय कोचिंग संस्था छू लो आसमान को जाता है। इस संस्था में बच्चों को निःशुल्क रहना, खाना और पढ़ाई की सुविधा मिलती है। NEET 2025 में इस संस्था से कुल 128 बच्चों ने परीक्षा दी, जिनमें से 39 सफल हुए और चार को MBBS की सीट मिलने जा रही है।

रत्ना कहती हैं, अगर 'छू लो आसमान' में दाखिला मिल जाए और मन लगाकर पढ़ाई की जाए, तो कोई भी सफलता से दूर नहीं रह सकता।÷ वहीं संतोष का कहना है, ÷जिला प्रशासन ने हमें न सिर्फ कोचिंग दी, बल्कि जीने का मकसद भी दिया।

ये सभी छात्र ऐसे इलाकों से हैं, जहां शिक्षा की पहुंच एक समय पर सपना हुआ करती थी। आज जब ये बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो पूरे बस्तर के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं।

छत्तीसगढ़ सरकार विकास, विश्वास और सुरक्षा के सिद्धांत पर नक्सल प्रभावित इलाकों में काम कर रही है। दंतेवाड़ा जिला प्रशासन और पुलिस ने मिलकर छू लो आसमान जैसी संस्थाएं बनाई हैं, ताकि आदिवासी अंचल के बच्चे भी डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बन सकें। इन संस्थाओं में न केवल शिक्षा दी जाती है, बल्कि रहने, खाने, मानसिक सहयोग, करियर काउंसलिंग और परीक्षा की तैयारी भी की जाती है।

रत्ना और संतोष की कामयाबी बताती है कि हालात कितने भी मुश्किल हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। ये दोनों अब अपने गांव के पहले डॉक्टर बनेंगे। नक्सलगढ़ में जहां कभी बंदूकें बोलीं करती थीं, अब वहां से नीट और जेईई के सफल उम्मीदवार निकल रहे हैं। ये बदलाव न सिर्फ शिक्षा की ताकत को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि शासन-प्रशासन की नीतियां और स्थानीय समाज की इच्छाशक्ति जब एकजुट होती है, तो नक्सलवाद पर भी जीत पाई जा सकती है।

रत्ना रामू और संतोष पोडियम जैसे छात्र अब न सिर्फ अपने गांव के लिए प्रेरणा बन चुके हैं, बल्कि पूरे बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए गर्व का विषय हैं। इनकी कहानी हर उस बच्चे को प्रेरणा दे सकती है जो कठिन परिस्थितियों में भी बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखता है।

अब वह दिन दूर नहीं जब बस्तर के हर गांव से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर या शिक्षक निकलेगा, और नक्सलगढ़ शिक्षा और विकास की नई गाथा लिखेगा।

बलौदा की पहाड़ियों पर कंटूर ट्रेंच से जल संरक्षण और हरियाली की दिशा में बड़ा कदम

मनरेगा के तहत हेडसपुर पंचायत के गोसाई पहाड़ में चल रहा निर्माण कार्य, ग्रामीणों को मिला रोजगार

छत्तीसगढ़ सरकार के मोर गांव मोर पानी अभियान के अंतर्गत जल संरक्षण और पर्यावरण संवर्धन की दिशा में लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दूरदर्शी सोच और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में की जा रही पहल के अंतर्गत जांजगीर-चांपा जिले के बलौदा विकासखंड में स्थित ग्राम पंचायत हेडसपुर के गोसाई पहाड़ पर स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहा है।

इस परियोजना को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है। गोसाई पहाड़ पर चल रहे इस कार्य के लिए 6 लाख 46 हजार 973 रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके अंतर्गत कुल 2,050 कंटूर ट्रेंच बनाए जा रहे हैं। इस निर्माण कार्य से न केवल पर्यावरण को लाभ मिलेगा, बल्कि स्थानीय ग्रामीणों को भी भरपूर रोजगार के अवसर मिल रहे हैं।

क्या है कंटूर ट्रेंच तकनीक?

कंटूर ट्रेंच एक आधुनिक लेकिन सुलभ जल संरक्षण तकनीक है, जो विशेष रूप से ढलान वाली ज़मीनों पर कारगर साबित होती है। इसमें समान ऊंचाई पर खाइयाँ खोदी जाती हैं ताकि वर्षा का जल एक स्थान पर रुके और ज़मीन में धीरे-धीरे समा जाए। इससे दोहरे लाभ होते हैं — एक तो जलस्रोतों को संजीवनी मिलती है, और दूसरा, भूमि कटाव जैसे प्राकृतिक नुकसान से बचाव होता है।

स्टेगर्ड कंटूर ट्रेंच की विशेषता यह है कि इन खाइयों को ज़िगज़ैग पैटर्न में बनाया जाता है, जिससे वर्षा जल का प्रवाह नियंत्रित रहता है और यह पूरी तरह जमीन में अवशोषित हो जाता है। इससे पहाड़ी क्षेत्रों में नमी का स्तर बना रहता है और हरियाली लौटने की प्रक्रिया में तेज़ी आती है।

ग्रामीणों को मिला रोज़गार, गांव की बदल रही तस्वीर

इस परियोजना का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि इसके तहत स्थानीय मनरेगा श्रमिकों को प्राथमिकता दी जा रही है। इस पहल से गांव के दर्जनों परिवारों को रोज़गार मिला है, जिससे उनकी आजीविका को मजबूती मिली है। मजदूरी करते हुए गांव के लोग अब अपने ही संसाधनों को पुनर्जीवित करने में भागीदार बन रहे हैं।

यह परियोजना केवल श्रमदान नहीं, बल्कि ग्रामीण आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ाया गया एक ठोस कदम है। महिलाएं और युवा भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे समाज में सामूहिक चेतना और भागीदारी की भावना को बल मिल रहा है।

पर्यावरण संरक्षण और जल पुनर्भरण की ओर

गोसाई पहाड़ पर किए जा रहे कंटूर ट्रेंच निर्माण कार्य का प्रमुख उद्देश्य वर्षा जल का संरक्षण कर जलस्तर को बढ़ाना है। इस क्षेत्र में पहले जल की भारी किल्लत रहती थी और गर्मियों में कुंए और हैंडपंप सूख जाते थे। अब इस परियोजना से उम्मीद जगी है कि न केवल भूजल स्तर बढ़ेगा, बल्कि आसपास के जल स्रोत भी पुनर्जीवित होंगे।

प्राकृतिक नालों, सूखे पड़े टीलों और बंजर भूमि में हरियाली लौटेगी, जिससे छोटे-छोटे जलाशयों और चरागाहों का निर्माण भी संभव हो सकेगा। इसके अलावा यह परियोजना मिट्टी की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगी, जिससे कृषि कार्यों को भी बढ़ावा मिलेगा।

मोर गांव मोर पानी- एक जनआंदोलन का रूप

मोर गांव मोर पानी अभियान अब केवल सरकारी योजना नहीं रह गई है, बल्कि यह एक जनआंदोलन का स्वरूप ले चुकी है। इस अभियान ने ग्रामीणों में अपने जलस्रोतों की रक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाई है।

यह पहल न केवल जल आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है, बल्कि सतत विकास की बुनियाद भी रख रही है। गांव के लोग अब समझने लगे हैं कि यदि जल होगा, तो जीवन होगा, खेती होगी और समृद्धि भी आएगी। कंटूर ट्रेंच जैसे जल संरक्षण उपायों को और विस्तार देने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ के अन्य पहाड़ी और अर्ध-बंजर इलाकों में भी इस तकनीक को अपनाकर बड़े पैमाने पर हरियाली और जल संरक्षण का जाल बुना जा सकता है।

जिला प्रशासन, पंचायतें और स्वयंसेवी संस्थाएं मिलकर यदि इस दिशा में सामूहिक प्रयास करें, तो छत्तीसगढ़ को जल संरक्षण में एक रोल मॉडल के रूप में स्थापित किया जा सकता है। साथ ही यह जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भी कारगर सिद्ध होगा।

गोसाई पहाड़ पर कंटूर ट्रेंच का निर्माण केवल खाइयों की खुदाई नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक नींव रखने जैसा कार्य है। यह छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों के लिए एक प्रेरक उदाहरण है कि सीमित संसाधनों में भी यदि संकल्प और सहभागिता हो, तो जल, जंगल और जमीन को संजोया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की नीति और नेतृत्व में राज्य की ग्रामीण जल नीति नये आयामों को छू रही है और 'मोर गांव मोर पानी' अभियान इसका जीवंत प्रमाण बन चुका है।

बस्तर के बच्चों का स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध- मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित अंचल बस्तर में बदलाव की बयार बह रही है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों का उद्देश्य केवल विकास नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों को पंख देना भी है। इसी म में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में छत्तीसगढ़ विधानसभा में नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत राजधानी रायपुर के शैक्षणिक भ्रमण पर आए सुकमा जिले के बच्चों से आत्मीय मुलाकात की।

आत्मीय संवाद, प्रेरणादायक संदेश

राजधानी रायपुर की चहल-पहल, सरकारी तंत्र के कामकाज, और आधुनिक संरचनाओं को देखने-समझने का अनुभव इन बच्चों के लिए अविस्मरणीय रहा। मुख्यमंत्री श्री साय ने इन बच्चों से मुस्कराते हुए संवाद किया और पूछा, बस्तर के शेर बच्चों ने रायपुर के जंगल सफारी में शेर देखा या नहीं? इस सजीव और हास्य से भरपूर संवाद ने माहौल को खुशनुमा बना दिया और बच्चों के चेहरों पर आत्मविश्वास की चमक बिखेर दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर के बच्चों का स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं को बस्तर के सुदूर कोनों तक पहुँचाने के लिए संकल्पित है।

नियद नेल्लानार योजना- बच्चों के सपनों को नया क्षितिज

नियद नेल्लानार योजना के अंतर्गत इस बार सुकमा जिले की पाँच सुदूर ग्राम पंचायतों — पालाचलमा, पोटकपल्ली, एलमागुंडा, ताड़मेटला एवं गोलापल्ली — के 100 स्कूली बच्चों को रायपुर भ्रमण का अवसर मिला। यह कार्यक्रम बच्चों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है, उन्हें नई चीज़ें देखने और सीखने की प्रेरणा देता है।

भ्रमण के दौरान बच्चों को मंत्रालय, जंगल सफारी, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसे प्रमुख स्थलों का अवलोकन कराया गया, जिससे उन्हें राज्य के प्रशासनिक और बुनियादी ढांचे को समझने का व्यावहारिक अनुभव मिला।

आत्मनिर्भर बस्तर-एक विकासशील दृष्टिकोण

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार आत्मनिर्भर बस्तर की संकल्पना को मूर्त रूप दे रही है। बस्तर के युवाओं को दुग्ध उत्पादन जैसे कार्यों से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। सरकार स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा कर रही है, ताकि क्षेत्र के बच्चों और युवाओं को अपने ही गाँव-शहर में सम्मानजनक आजीविका मिल सके।

श्री साय ने यह भी उल्लेख किया कि सुदूर अंचलों में सुरक्षाबलों के कैंप स्थापित हो रहे हैं और इसके साथ ही चौतरफा विकास के द्वार खुल रहे हैं। शासकीय राशन दुकानें अब ज़्यादातर स्थानों पर खुल चुकी हैं, जिससे आम नागरिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगा है।

बस्तर के उज्ज्वल कल की ओर

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि निकट भविष्य में बस्तर पूरी तरह से नक्सलमुक्त होगा और वहाँ का हर बच्चा बिना भय, बिना भटकाव, शिक्षा और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि

राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तकों तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उन्हें अनुभव, अवलोकन और आत्मविश्वास से जोड़ना चाहती है।

सहभागिता और समर्थन

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, वन मंत्री श्री केदार कश्यप और विधायकगण श्री ईश्वर साहू एवं श्री सुशांत शुक्ला की उपस्थिति ने इस मुलाकात को और भी विशेष बना दिया। यह संदेश गया कि सरकार के उच्चतम स्तर पर बस्तर के भविष्य—वहाँ के बच्चों—के प्रति गहरी प्रतिबद्धता है। बस्तर का भविष्य वहाँ के बच्चों में बसता है, और राज्य सरकार इस भविष्य को उज्ज्वल, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने के लिए सतत प्रयासरत है। नियद नेल्लानार योजना जैसे प्रयास केवल भ्रमण नहीं, बल्कि नए दृष्टिकोण, नए सपनों और नए आत्मविश्वास की नींव हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की यह पहल बस्तर के बच्चों को यह यकीन दिलाती है कि उनका भविष्य राजधानी में बैठे लोगों की प्राथमिकता है — और वह भविष्य सुनहरा ही नहीं, गरिमामय भी होगा।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रयासों से ऐतिहासिक स्वीकृति
चावल उपार्जन लक्ष्य में 8 लाख मीट्रिक टन की वृद्धि

एक ऐतिहासिक निर्णय जो किसानों के हितों को देगा नया संबल

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोपरि मानती है। उनके सतत एवं निर्णायक प्रयासों से केंद्र सरकार ने वर्ष 2024-25 के लिए चावल उपार्जन लक्ष्य को 70 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 78 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। यह न केवल राज्य के किसानों के लिए एक बड़ी राहत है, बल्कि छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति के लिए भी अत्यंत सकारात्मक संकेत है।

इतिहास में पहली बार- रिकॉर्ड धान उपार्जन

छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर 149.25 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया है, जो राज्य गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस ऐतिहासिक उपार्जन को कुशल प्रबंधन द्वारा कस्टम मिलिंग के माध्यम से त्वरित रूप से निराकृत किया जा रहा है।

- केन्द्रीय पूल हेतु पूर्व निर्धारित लक्ष्य- 70 लाख मी. टन
- अब स्वीकृत संशोधित लक्ष्य- 78 लाख मी. टन
- कुल कस्टम मिलिंग हेतु निर्धारित धान- 118.17 लाख मी. टन

नीलामी से किसानों को राहत

राज्य सरकार ने उपार्जित अतिरिक्त धान को नीलामी के माध्यम से निराकृत करने का दूरदर्शी निर्णय लिया है। इसके तहत अब तक 19 लाख मीट्रिक टन धान के लिए बायर ऑर्डर जारी हो चुके हैं, और उसका त्वरित उठाव भी क्रेताओं एवं मिलरों द्वारा किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में खाद्य विभाग ने संग्रहण केंद्रों पर शेष धान की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए हैं।

केंद्र के साथ समन्वय के उत्कृष्ट परिणाम

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने 24 जून 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर चावल उपार्जन लक्ष्य में वृद्धि का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री के इस निरंतर संवाद और केंद्र के साथ तालमेल के फलस्वरूप 18 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया।

राजकोषीय हानि से मिली बड़ी राहत

अगर चावल उपार्जन लक्ष्य में यह वृद्धि नहीं होती, तो राज्य सरकार को लगभग 1200 करोड़ रुपये की संभावित वित्तीय हानि उठानी पड़ती। केंद्र सरकार के इस निर्णय से न केवल किसानों का धान समर्थन मूल्य पर उठाया जा सका, बल्कि राज्य की राजकोषीय स्थिति को भी मज़बूती मिली है।

किसानों और मिलर्स को मिला भरोसा

मुख्यमंत्री श्री साय ने केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि यह निर्णय केंद्र और राज्य की समन्वित किसान-हितैषी नीति का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेश के मिलर एसोसिएशन और किसानों की मांगों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की प्रतिबद्धता दोहराई।

यह निर्णय क्यों है विशेष?

पहलू	विवरण
किसानों को लाभ	एक-एक दाना धान की खरीदी सुनिश्चित
राज्य की अर्थव्यवस्था	1200 करोड़ रु. की संभावित हानि से बचाव
सार्वजनिक वितरण प्रणाली	योजनाओं के संचालन में सहायता
केंद्र-राज्य समन्वय	कृषि क्षेत्र में संयुक्त नीति की मिसाल

चावल उपार्जन लक्ष्य में 8 लाख मीट्रिक टन की यह ऐतिहासिक वृद्धि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता और किसान-हितैषी दृष्टिकोण की परिचायक है। यह निर्णय न केवल लाखों किसानों की आजीविका को संबल प्रदान करेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ को कृषि के क्षेत्र में एक नए युग की ओर अग्रसर करेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की सरकार है — और यह निर्णय उसका जीवंत प्रमाण है।

मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना

ग्रामीण अधोसंरचना के सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी कदम

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां जनसंख्या का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण भारत की प्रगति के बिना समग्र विकास की कल्पना अधूरी है। इसी दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना प्रारंभ की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मौलिक और आवश्यक अधोसंरचनाओं का निर्माण कर लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। यह योजना ग्रामों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार की गई है, जो एक समावेशी और स्थायी विकास की परिकल्पना को साकार करती है।

योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना का मूल उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नलिखित बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराना है-

- सामाजिक व भौतिक अधोसंरचना का विकास
- ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार
- ग्राम पंचायतों की कार्यक्षमता को बढ़ाना
- स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करना
- स्वच्छता, जलापूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और खेलकूद के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माण

प्रमुख गतिविधियाँ एवं अधोसंरचनात्मक निर्माण

इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों की सूची अत्यंत व्यापक है, जो ग्रामीण जीवन के विविध पहलुओं को छूती है। ये कार्य स्थानीय आवश्यकताओं और जनता की प्राथमिकताओं के अनुरूप तय किए जाते हैं। नीचे प्रमुख गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है-

1. तालाबों का सौंदर्यीकरण

ग्रामों में पारंपरिक जल स्रोतों का संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। योजना के अंतर्गत पुराने तालाबों की सफाई, घाट निर्माण, बैठने की व्यवस्था, पौधरोपण तथा प्रकाश व्यवस्था जैसे कार्य किए जाते हैं।

2. आंतरिक पुल-पुलिया निर्माण

ग्रामों में बरसात के मौसम में आवागमन की समस्या आम है। आंतरिक रास्तों पर छोटे पुल-पुलियों के निर्माण से गांवों का संपर्क सुगम बनता है, जिससे आर्थिक और सामाजिक गतिविधियाँ निर्बाध रूप से चल सकती हैं।

3. पंचायत भवनों का सुदृढ़ीकरण

पंचायत भवनों में अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, विद्युत व्यवस्था, बैठक कक्ष, फर्नीचर आदि की व्यवस्था से ग्राम पंचायतों की कार्यशीलता में वृद्धि होती है। इससे ई-गवर्नेंस को भी बल मिलता है।

4. आंगनबाड़ी भवन निर्माण (बाउंड्रीवाल सहित)

बच्चों के पोषण और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण अति आवश्यक है। योजना के अंतर्गत नए भवनों का निर्माण, चारदीवारी, पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है।

5. गली एवं नाली निर्माण

गांवों की गलियों को कांक्रीट से पक्का कर और नालियों का निर्माण कर न सिर्फ आवागमन सुगम बनाया जाता है, बल्कि स्वच्छता को भी बढ़ावा मिलता है। जलजमाव की समस्या का समाधान इसी से होता है।

6. मुक्ति धाम एवं निर्मलाघाट निर्माण

अंतिम संस्कार स्थलों का सौंदर्यीकरण, बैठने की जगह, छाया शेड, जल की सुविधा आदि सुनिश्चित कर सम्मानजनक विदाई का वातावरण निर्मित किया जाता है।

7. हाट-बाजार एवं अटल बाजार का विकास

ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले हाट बाजारों को व्यवस्थित करने हेतु योजना के अंतर्गत पक्की दुकानें, शेड, पक्की सड़कें, ड्रेनेज प्रणाली तथा चबूतरों का निर्माण किया जाता है। इससे स्थानीय व्यापार को बढ़ावा

मिलता है।

8. सामुदायिक भवन, रंगमंच एवं अटल समरसता भवन

ग्रामवासियों की बैठक, सांस्कृतिक आयोजनों एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए सामुदायिक भवनों तथा रंगमंच का निर्माण ग्रामीण जीवन में सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देता है।

9. यात्री प्रतीक्षालय एवं मिनी स्टेडियम निर्माण

गांवों में बस स्टॉप या यात्री प्रतीक्षालयों का निर्माण ग्रामीण यात्रियों के लिए सहूलियत भरा होता है। वहीं मिनी स्टेडियम निर्माण से युवाओं को खेलकूद की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, जिससे उनकी ऊर्जा सकारात्मक दिशा में लगती है।

10. अमर बलिदानी स्मारक निर्माण

गांवों से देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीरों की स्मृति में स्मारक बनाए जाते हैं, जिससे भावी पीढ़ियाँ उनके बलिदानों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें।

डिजिटल युग की ओर अग्रसर पंचायतें - ई-पंचायत

योजना के अंतर्गत ई-पंचायत प्रणाली को सशक्त करने हेतु आवश्यक उपकरण, प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। इससे पारदर्शिता बढ़ती है और ग्राम स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में दक्षता आती है।

पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों और सचिवों के प्रशिक्षण हेतु राज्य, जिला एवं जनपद स्तर पर प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण किया जाता है, ताकि वे शासन की योजनाओं को सही रूप में लागू कर सकें।

एकीकृत सुविधा केंद्र एवं साइन बोर्ड निर्माण

ग्रामवासियों को सरकारी सेवाओं की जानकारी एवं पहुंच एक स्थान पर देने के उद्देश्य से एकीकृत सुविधा केंद्र बनाए जाते हैं। साथ ही, सार्वजनिक स्थलों पर साइन बोर्ड लगाकर कार्यों की जानकारी देना पारदर्शिता और जन-जागरूकता का प्रतीक है।

FRA Site Development के लिए विशेष प्रावधान

जिन जिलों में DMF (District Mineral Foundation) नहीं है, वहाँ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में Forest Rights Act (FRA) के अंतर्गत भूमि पट्टा धारकों के लिए विकास कार्य किए जाते हैं। इस उद्देश्य हेतु प्रति जिला 2.00 करोड़ की राशि योजना के तहत स्वीकृत की गई है। इसमें सिंचाई, आवास, सड़कों, बिजली आदि मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाता है।

योजना का सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव

इस योजना से गांवों में बहुआयामी परिवर्तन देखा गया है-

- ग्रामीण बुनियादी ढांचे का समग्र विकास
- रोजगार के अवसरों में वृद्धि (स्थानीय श्रमिकों को निर्माण कार्य में प्राथमिकता)
- महिला सशक्तिकरण (आंगनबाड़ी, पंचायत भवन आदि में महिलाओं की भागीदारी)
- ग्रामों की स्वच्छता एवं पेयजल की उपलब्धता में सुधार
- खेल, संस्कृति एवं सामाजिक गतिविधियों को प्रोत्साहन
- स्थानीय संसाधनों का बेहतर उपयोग

मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना न केवल अधोसंरचना निर्माण का कार्य करती है, बल्कि यह ग्रामवासियों में आत्मनिर्भरता, स्वच्छता, सामाजिक समरसता और स्थानीय प्रशासन की दक्षता को भी बढ़ाती है। यह योजना शासन की गांव की ओर चलो नीति को साकार करती है, जिसमें ग्रामों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना लक्ष्य है।

इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र एक सशक्त, स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध पहचान के रूप में उभरेंगे। सरकार, पंचायत प्रतिनिधि और आमजन के सामूहिक प्रयासों से यह सपना जल्द ही साकार हो सकता है।

शुभांशु शुक्ला- अंतरिक्ष में भारत का नया चेहरा....

प्रारंभिक जीवन और शिक्षा

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जन्म उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। वे अपने परिवार में तीन भाई-बहनों में सबसे छोटे हैं। उनके पिता श्री शंभू दयाल शुक्ला एक सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, जबकि उनकी माता श्रीमती आशा शुक्ला एक गृहिणी हैं। बचपन से ही शुभांशु पढ़ाई में कुशाग्र और विज्ञान के प्रति उत्साही थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ के प्रतिष्ठित सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से प्राप्त की। वर्ष 1999 में हुए कारगिल युद्ध से प्रभावित होकर, देश सेवा का संकल्प लिया और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) तथा भारतीय नौसेना अकादमी की परीक्षा दी, जिसमें वे सफल हुए।

2005 में उन्होंने NDA से कंप्यूटर साइंस में विज्ञान स्नातक की डिग्री प्राप्त की और इसके बाद हैदराबाद स्थित वायुसेना अकादमी में उड़ान प्रशिक्षण लिया। जून 2006 में वे भारतीय वायु सेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में शामिल हुए।

भारतीय वायु सेना में सेवा

वर्ष 2025 तक शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन के पद तक पहुँच चुके हैं। वे एक उच्च प्रशिक्षित टेस्ट पायलट (परीक्षण पायलट) हैं और उन्होंने भारतीय वायुसेना के कई उन्नत लड़ाकू और परिवहन विमानों पर उड़ान भरी है, जिनमें प्रमुख हैं:-

- सुखोई Su-30MKI
- मिग-21, मिग-29
- जगुआर, BAE हॉक
- डोर्नियर 228, एंटोनोव AN-32

उनके पास 2,000 से अधिक घंटे का उड़ान अनुभव है — जो किसी भी टेस्ट पायलट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योग्यता मानी जाती है।

अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन और प्रशिक्षण

2019 में, इसरो के भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) के तहत शुभांशु शुक्ला को इंस्टीट्यूट ऑफ एयरोस्पेस मेडिसिन द्वारा अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयनित किया गया। वह चुने गए चार उम्मीदवारों में से एक थे।

2020 में उन्हें रूस के यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में बुनियादी प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। यह प्रशिक्षण 2021 में पूरा हुआ। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु स्थित इसरो अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण केंद्र में मिशन-विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की उपाधि भी प्राप्त की।

गगनयान मिशन और एक्सिओम-4 की उड़ान

27 फरवरी 2024 को इसरो ने आधिकारिक रूप से शुभांशु शुक्ला को भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की टीम में शामिल अंतरिक्ष यात्री के रूप में प्रस्तुत किया।

हालांकि गगनयान की उड़ान अभी प्रतीक्षित है, शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष उड़ान अनुभव के लिए अमेरिका की निजी कंपनी A&iom Space के मिशन A&-4 के लिए मिशन पायलट नियुक्त किया गया।

यह मिशन 25 जून 2025 को स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा स्थित नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ और 26 जून को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) से जुड़ा।

शुक्ला, इस मिशन में-

- भारत के पहले ISRO अंतरिक्ष यात्री बने जिन्होंने ISS का दौरा किया।
- राकेश शर्मा के 1984 मिशन के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बने।
- अंतरिक्ष में पहुँचे 634वें अंतरिक्ष यात्री बने।

अंतरिक्ष से राष्ट्र को संबोधन

शुक्ला का 25 जून 2025 को अंतरिक्ष से देश के नाम पहला संदेश बेहद भावुक था- हम 41 साल बाद एक बार फिर अंतरिक्ष में वापस आ गए हैं... यह यात्रा केवल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की नहीं है, बल्कि भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत है... आइए हम सब मिलकर भारत के मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत करें। जय हिंद! जय भारत!

अंतरिक्ष में गतिविधियाँ और प्रयोग-

A&–4 मिशन के दौरान शुक्ला ने–

- लगभग 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिनमें कम से कम 7 प्रयोग इसरो द्वारा नामित थे।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 28 जून को लाइव बातचीत की।
- 4 और 8 जुलाई को स्कूली छात्रों से हैम रेडियो के माध्यम से संवाद किया।
- 6 जुलाई को इसरो प्रमुख डॉ. वी. नारायणन से वैज्ञानिक प्रयोगों और गगनयान पर चर्चा की।

मिशन की लागत और प्रभाव

भारत सरकार ने शुक्ला की सीट के लिए लगभग ?548 करोड़ (65 मिलियन) का भुगतान किया। हालाँकि कुछ आलोचकों ने इस लागत पर सवाल उठाए, लेकिन इसरो और एक्सिओम स्पेस के अधिकारियों ने इस मिशन को सीखने, सहयोग और प्रशिक्षण का

अमूल्य अवसर बताया।

यह मिशन भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम को वैश्विक पटल पर एक नई पहचान देता है।

व्यक्तिगत जीवन

शुभांशु शुक्ला का विवाह उनकी स्कूल की सहपाठी और दंत चिकित्सक कामना मिश्रा से हुआ है। इस दंपत्ति का एक बेटा है। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि साधारण है, लेकिन उनके सपने असाधारण रहे हैं, जिन्हें उन्होंने अपने परिश्रम और समर्पण से साकार किया।

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की यात्रा एक प्रेरक गाथा है

साधारण पृष्ठभूमि से उठकर, देश की वायुसेना के श्रेष्ठ पायलट और अब अंतरिक्ष यात्री बनने तक की। उनका जीवन भारतीय युवाओं के लिए यह संदेश देता है कि दृढ़ निश्चय, मेहनत और समर्पण से कुछ भी असंभव नहीं है। उनका नाम अब न केवल भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में, बल्कि वैश्विक अंतरिक्ष यात्रियों की सूची में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया है।

शिव की भक्ति, योग की शक्ति...

बस्तर के नारायणपाल में लगाई चौपाल, जानी योजनाओं की जमीनी हकीकत

सावन केवल बारिश और हरियाली का नहीं, बल्कि शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का महीना है। यह वह समय है जब हम शिव की भक्ति में लीन होकर अपने तन और मन को भी शुद्ध करने का संकल्प लें। योगगुरु स्वामी रामदेव के अनुसार, सावन में भक्ति और शक्ति दोनों की साधना करने से न सिर्फ आध्यात्मिक बल बढ़ता है, बल्कि शारीरिक रोग भी दूर होते हैं।

सावन में योग का महत्व

बारिश के मौसम में इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, पाचन तंत्र धीमा पड़ता है और वायरल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में योग हमारे शरीर के हर अंग को सक्रिय करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है।

योगासन जो सावन में करें

- **सूर्य नमस्कार**- पूरे शरीर की एक्सरसाइज
- **भुजंगासन**- पाचन बेहतर, रीढ़ मजबूत
- **अनुलोम-विलोम**- फेफड़ों की क्षमता बढ़े, सांस संबंधी समस्या दूर
- **कपालभाति**- शरीर से विषैले तत्व बाहर
- **शवासन व ध्यान**- मानसिक शांति और तनाव मुक्ति

सावन में उपवास (फास्टिंग) का विज्ञान

स्वामी रामदेव कहते हैं, ÷फास्टिंग सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक तरीका है शरीर को डिटॉक्स करने का।÷ सावन के सोमवार को उपवास करने से शरीर की चयापचय प्रक्रिया (Metabolism) बेहतर होती है।

फास्टिंग के फायदे

- क्रॉनिक बीमारियों पर नियंत्रण
- ब्लड शुगर, थायरॉइड संतुलित
- इम्यून सिस्टम बेहतर
- उम्र लंबी होती है
- शरीर आत्मशुद्धि की ओर बढ़ता है

सावन के व्रत में क्या खाएं?

- मौसमी फल- जामुन, आम, केला, नाशपाती
- खूब पानी पिएं, हर्बल चाय लें
- उबला या भाप में पका खाना
- तला-भुना, मसालेदार भोजन न लें

सावन में विशेष सावधानियां

बारिश के मौसम में संक्रमण और एलर्जी का खतरा अधिक होता है। इस मौसम में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है।

बीमारियों से बचने के उपाय

- सुबह उठकर गुनगुना पानी पिएं
- एलोवेरा, आंवला, गिलोय का सेवन करें
- बाजार की चीजें खाने से बचें
- पानी को उबालकर ही पीएं
- रात में हल्का और सुपाच्य भोजन लें

सावन में आम समस्याएं

- वायरल और बैक्टीरियल संक्रमण
- सर्दी, खांसी, बुखार
- गले का संक्रमण
- अस्थमा, ब्रोंकाइटिस
- जोड़ दर्द, माइग्रेन

भोलेनाथ हैं आरोग्य के देवता

स्वामी रामदेव के अनुसार, शिव सिर्फ विनाश के नहीं, स्वास्थ्य और आरोग्यता के भी देवता हैं। वे प्रथम योगी हैं। उनकी भक्ति और योग का अभ्यास मिलकर न सिर्फ शरीर को निरोग बनाएंगे, बल्कि जीवन को भी संतुलित करेंगे। सावन आत्मिक और शारीरिक शुद्धि का उपयुक्त समय है। इस पवित्र महीने में शिव की भक्ति के साथ अगर आप योग, प्राणायाम और फास्टिंग को नियमित रूप से अपनाएं, तो कई बीमारियों से बचा जा सकता है। तन-मन की शुद्धि से ही सच्ची भक्ति संभव है।

योगासन / प्राणायाम	**लाभ**
सूर्य नमस्कार	पूरे शरीर की एक्सरसाइज
भुजंगासन	पाचन ठीक, रीढ़ मजबूत
अनुलोम-विलोम	सांस की शक्ति, फेफड़े स्वस्थ
कपालभाति	शरीर डिटॉक्स, वजन कम
शवासन व ध्यान	मन शांत, नींद बेहतर

अब 9 कैरेट गोल्ड पर भी हॉलमार्क जरूरी-सरकार का बड़ा फैसला

भारत में सोने की खरीदारी न केवल एक परंपरा है, बल्कि यह निवेश का एक महत्वपूर्ण साधन भी माना जाता है। लेकिन उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए सोने की शुद्धता को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी दिशा में भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है- अब 9 कैरेट गोल्ड पर भी हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है। पहले केवल 14, 18, और 22 कैरेट तक के सोने पर हॉलमार्किंग अनिवार्य थी, लेकिन अब यह दायरा और व्यापक हो गया है।

हॉलमार्किंग क्या है?- हॉलमार्किंग वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत सोने या चांदी की वस्तुओं की शुद्धता और गुणवत्ता की सरकारी मान्यता प्राप्त लैब में जांच की जाती है, और फिर एक प्रमाणित चिह्न (मार्क) लगाया जाता है। यह प्रमाणित करता है कि आभूषण में बताए गए कैरेट के अनुरूप शुद्धता है।

नया क्या हुआ है?- भारतीय मानक ब्यूरो ने हाल ही में घोषणा की है कि-अब 9 कैरेट सोने के आभूषण और वस्तुओं पर भी हॉलमार्किंग अनिवार्य होगी। इससे पहले भारत में मुख्य रूप से 14, 18, और 22 कैरेट के गहनों की हॉलमार्किंग ही मान्य थी। अब 9 कैरेट को भी इसमें शामिल कर लिया गया है।

9 कैरेट गोल्ड क्या होता है?- 9 कैरेट गोल्ड यानी 37.5त्न शुद्ध सोना। बाकी का भाग अन्य धातुओं (जैसे तांबा, चांदी, जिंक आदि) का मिश्रण होता है। इसे आमतौर पर सस्ता विकल्प माना जाता है और यह आजकल फैशन ज्वेलरी या हल्के आभूषणों में लोकप्रिय होता जा रहा है।

यह फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

1. **उपभोक्ताओं की सुरक्षा-** हॉलमार्क के जरिए ग्राहक को यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि वह जो खरीद रहा है, वह सही गुणवत्ता का है।
2. **धोखाधड़ी में कमी-** अब तक कई ज्वेलर्स कम शुद्धता का सोना ज्यादा कैरेट बताकर बेचते थे। हॉलमार्किंग अनिवार्य होने से यह चलन रुकेगा।
3. **9 कैरेट ज्वेलरी की लोकप्रियता-** शहरी और युवा वर्ग में सस्ते और हल्के गहनों की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में 9 कैरेट की मांग बढ़ रही है और हॉलमार्क इसे अधिक विश्वसनीय बनाएगा।
4. **अंतरराष्ट्रीय मानकों की दिशा में कदम-** कई देशों में पहले से ही 9 कैरेट तक की हॉलमार्किंग प्रचलित है। यह निर्णय भारत को उस दिशा में आगे ले जाता है।

हॉलमार्क में कौन-कौन से संकेत होते हैं? हॉलमार्क लगे गहनों पर आमतौर पर निम्नलिखित जानकारी होती है-

1. BIS का लोगो
2. कैरेट या शुद्धता का स्तर (जैसे 22य़, 18य़, अब 9य़)
3. हॉलमार्किंग केंद्र की पहचान संख्या
4. ज्वेलर्स की पहचान संख्या

कब से लागू होगा ये नियम? सरकार ने इसकी तत्काल प्रभाव से शुरुआत की घोषणा की है, हालांकि ज्वेलर्स को आवश्यक तैयारी और अवसंरचना सुधार के लिए कुछ माह का समय दिया जा सकता है। BIS द्वारा इसकी विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी।

इस फैसले का असर किस पर पड़ेगा?

वर्ग	असर
उपभोक्ता	अधिक पारदर्शिता और सुरक्षा
ज्वेलर्स	अधिक जवाबदेही, लेकिन प्रक्रिया में बदलाव
सरकार	उपभोक्ता संरक्षण में एक बड़ी उपलब्धि
रोजगार	परीक्षण और हॉलमार्किंग सुविधाओं में रोजगार के अवसर

चुनौतियां भी हैं-

- छोटे दुकानदारों के लिए हॉलमार्किंग की लागत और प्रक्रियात्मक झंझट।
- ग्रामीण क्षेत्रों में हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या सीमित है।
- 9 कैरेट की जांच की नई मशीनों और प्रक्रियाओं की आवश्यकता।

भारत सरकार का यह निर्णय निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के हित में उठाया गया एक सराहनीय कदम है। यह न केवल गुणवत्ता की गारंटी देगा, बल्कि ज्वेलरी उद्योग में पारदर्शिता और भरोसे को भी बढ़ाएगा। आने वाले समय में हॉलमार्किंग का दायरा और भी बढ़ सकता है, जिससे सोने की खरीदारी पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सुगम हो जाएगी।

आदिवासी महिला किसानों के सशक्तीकरण की ओर एक नई पहल
छत्तीसगढ़ में दुधारू पशु प्रदाय योजना का पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक बार फिर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों की महिला किसानों के सशक्तीकरण की दिशा में एक ठोस और प्रभावशाली कदम उठाया है। राज्य के छह जिलों- कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, सारंगढ़-बिलाईगढ़, जशपुर और बलरामपुर-रामानुजगंज- में दुधारू पशु प्रदाय योजना का पायलट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से आदिवासी समुदाय की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने, और पोषण सुधार की दिशा में सरकार ने एक नई उम्मीद जगाई है।

योजना का उद्देश्य और स्वरूप

दुधारू पशु प्रदाय योजना का मुख्य उद्देश्य आदिवासी महिला किसानों की आय में वृद्धि, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन, और पारिवारिक पोषण स्तर में सुधार करना है। इसके तहत प्रत्येक महिला किसान को साहीवाल नस्ल की दो दुधारू गायें प्रदान की जा रही हैं। साहीवाल नस्ल भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारू गायों में से एक मानी जाती है, जो कम देखभाल में भी अधिक दूध देती है और जलवायु अनुकूलन में सक्षम होती है।

इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा किया जा रहा है, जिसमें तकनीकी सहयोग राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) की सहायक संस्था NDDB डेयरी सर्विसेस द्वारा प्रदान किया जा रहा है।

कांकेर में हुआ योजना का शुभारंभ

योजना का औपचारिक शुभारंभ कांकेर जिले के बड़गांव (पखांजूर) में हुआ, जहां आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में 75 आदिवासी महिला किसानों को दुधारू गायें प्रदान की गईं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद श्री भोजराज नाग ने योजना को महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया।

उन्होंने कहा कि यह योजना आदिवासी अंचल की महिलाओं को दूध व्यवसाय से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। विधायक श्री विक्रम उसेंडी ने भी कार्यक्रम में शिरकत कर महिलाओं को शुभकामनाएं दीं और योजना के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डाला।

वित्तीय संरचना- भागीदारी आधारित मॉडल

इस योजना की सबसे उल्लेखनीय विशेषता इसकी भागीदारी आधारित वित्तीय संरचना है। इसमें तीन प्रमुख घटक शामिल हैं-

- 50 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है।
- 40 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर ऋण के रूप में प्रदान की जा रही है।
- शेष 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी महिला किसान स्वयं वहन करेंगी।

इस योजना में यह प्रावधान किया गया है कि ऋण की वसूली दूध के

विक्रय से की जाएगी, जिससे किसानों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार न पड़े।

नि:शुल्क सुविधाएं और तकनीकी सहयोग

दुधारू पशु प्रदान करने के साथ-साथ राज्य सरकार एक वर्ष तक मुफ्त सेवाएं भी उपलब्ध करा रही है, जिससे पशुपालन में गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित हो सके। इन सुविधाओं में शामिल हैं-

- दुधारू पशुओं का बीमा
- पशु स्वास्थ्य निगरानी एवं नियमित चिकित्सा सेवा
- प्रजनन सुविधा
- साइलेज चारा, पौष्टिक आहार एवं खनिज मिश्रण
- वैज्ञानिक पशुपालन पर प्रशिक्षण

इन तकनीकी सेवाओं के लिए राज्य की पशु चिकित्सा टीमों को सक्रिय रूप से लगाया गया है, ताकि हर लाभार्थी को समय पर मदद मिल सके।

समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की यह योजना न केवल आर्थिक विकास का माध्यम है, बल्कि सामाजिक न्याय और लैंगिक समानता की दिशा में भी एक मजबूत कदम है। वनांचल में रहने वाली आदिवासी महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़ना, उन्हें न केवल आय का स्रोत प्रदान करता है, बल्कि उन्हें अपने निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान भी देता है।

यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उस स्वरूप को पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसमें महिला शक्ति की सहभागिता को केवल सहयोगी नहीं, बल्कि नेतृत्वकारी भूमिका में देखा जा रहा है।

दुधारू पशु प्रदाय योजना

छत्तीसगढ़ सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जो पोषण, रोजगार, महिला सशक्तीकरण और दुग्ध उत्पादन जैसे कई मोर्चों पर सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम है। यदि यह पायलट प्रोजेक्ट सफल होता है, तो आने वाले समय में इसे पूरे राज्य में विस्तार दिया जा सकता है, जिससे हजारों ग्रामीण परिवारों का जीवन स्तर सुधर सकेगा।

छत्तीसगढ़ की यह पहल निश्चित रूप से अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बनेगी, जो यह दर्शाएगी कि योजनाएं जब नीतियों से जुड़कर ज़मीन पर उतरती हैं, तो वास्तविक बदलाव की शुरुआत होती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव ला रहीं है समूह की दीदियां

छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएं अब स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशों के अनुरूप महिलाओं को स्व-रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन जशपुर ने उल्लेखनीय पहल की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जिले में 11,559 स्व-सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिनसे 1,24,117 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और विभिन्न आजीविका मूलक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता निभाने के साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव ला रही है।

स्व-सहायता समूह की महिलाएं अब परंपरागत कृषि को आधुनिक एवं प्राकृतिक पद्धतियों से जोड़ रही हैं। बीज उपचार, द्रव और घन जीवामृत, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र जैसी जैविक विधियों के निर्माण और उपयोग हेतु उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। इससे जहां खेती की लागत घटी है और उत्पादकता में भी सुधार हुआ है। राज्य शासन की विभिन्न योजनाएं जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम विकास एवं मनरेगा के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों को जोड़कर उनके लिए आय के नए स्रोत सृजित किए जा रहे हैं। सामुदायिक निधियों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, वहीं बैंक लिंकेज और मुद्रा लोन जैसी योजनाओं से दीदियों को आजीविका गतिविधियों को बढ़ाने में भरपूर सहायता मिल रही है। समूहों से जुड़ी कई महिलाएं आज दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं। समूह की सहायता से कुछ महिलाएं अब खुद की दुकान चला रही हैं, तो कुछ दुग्ध उत्पादन और मछली पालन कर रही हैं। इससे न केवल उनके परिवार की आय में वृद्धि हुई है, बल्कि उनमें एक नया आत्मविश्वास जगा है।

स्व सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को संगठित कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों से जोड़ना छत्तीसगढ़ सरकार के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दूरदर्शिता और नेतृत्व में यह पहल जशपुर जिले के विकास को नई दिशा दे रही है। स्व-सहायता समूहों की दीदियों का यह प्रयास न केवल उनके जीवन को संवार रहा है, बल्कि एक समावेशी और आत्मनिर्भर भारत की ओर एक महत्वपूर्ण कदम भी सिद्ध हो रहा है।

छत्तीसगढ़ बना स्किल हब की ओर अग्रसर- विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 बना ऐतिहासिक उपलब्धियों का साक्षी...

भविष्य की ओर बढ़ते छत्तीसगढ़ ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की है। भिलाई स्थित रूंगटा यूनिवर्सिटी में आयोजित विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 का समापन एक गौरवपूर्ण उपलब्धि के साथ हुआ, जिसमें 8183 युवाओं को एक सप्ताह में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस प्रयास को गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा प्रमाणित किया गया, जिससे राज्य की कौशल विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा, हम विकसित भारत-विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्यरत हैं, और इसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाएगा, और रूंगटा यूनिवर्सिटी ने नि:शुल्क प्रशिक्षण देकर युवाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रेरणा दी है।

भिलाई- इस्पात नगरी से स्किल नगरी तक का सफर

मुख्यमंत्री ने भिलाई को मिनी इंडिया बताते हुए कहा कि यह शहर न केवल इस्पात उत्पादन का केंद्र है, बल्कि अब शिक्षा और तकनीकी कौशल का भी मुख्य केन्द्र बन रहा है। उन्होंने रूंगटा यूनिवर्सिटी की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान राज्य सरकार के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ को ग्लोबल स्किल हब बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

25 वर्ष की विकास यात्रा और सुशासन की दिशा में कदम

छत्तीसगढ़ की रजत जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की 25 वर्षों की विकास यात्रा को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में उच्च शिक्षा संस्थानों का विस्तार हुआ और वर्तमान में राज्य में 15 मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, ट्रिपल आईटी, सिपेट, एम्स और लॉ यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान कार्यरत हैं।

वर्तमान सरकार द्वारा डिजिटलीकरण, पारदर्शिता, और राजस्व वृद्धि के लिए किए गए कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकांश शासकीय सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता आई है और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हुआ है।

स्किल इंडिया मिशन से जुड़ा छत्तीसगढ़

निवेश और रोजगार के नए द्वार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्किल इंडिया मिशन आज फलीभूत हो रहा है। उन्होंने बताया कि जब यह मिशन शुरू हुआ, तब भारत विश्व की 10वीं अर्थव्यवस्था था, और आज यह चौथे स्थान पर है। यह भारत के युवाओं की क्षमता और अवसरों के सृजन का प्रमाण है।

मेगा प्लेसमेंट कैंप्स, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, और राज्य की नई औद्योगिक नीति ने रोजगार और कौशल के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। ऐसी इकाइयों को अनुदान देने की नीति बनाई गई है जो 1000 से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार देंगी। बस्तर और सरगुजा जैसे पिछड़े क्षेत्रों में अतिरिक्त रियायतें प्रदान की गई हैं।

औद्योगिक विकास की रफ्तार- निवेश और नवाचार को प्रोत्साहन

राज्य सरकार द्वारा लागू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम से निवेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब तक 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि नवा रायपुर में फार्मास्युटिकल हब की स्थापना और प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास हो चुका है। इसके साथ ही भारत का पहला एआई डाटा सेंटर पार्क भी नवा रायपुर में स्थापित किया गया है।

युवा कौशल उत्सव की उपलब्धियाँ- वैश्विक मानकों से कदमताल

इस उत्सव के दौरान-

- 8183 युवाओं को विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण दिया गया।
- गूगल, आईबीएम, और इंटरनेशनल काउंसिल के साथ संयुक्त डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।
- हार्वर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर हुए।
- वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे एक सप्ताह में सबसे अधिक युवाओं को प्रशिक्षित करने का रिकॉर्ड घोषित किया।

समारोह में 25 चयनित प्रतिभागियों को मुख्यमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

नेताओं और विश्वविद्यालय की प्रतिक्रियाएँ

कार्यक्रम में सांसद श्री विजय बघेल और विधायक श्री रिकेश सेन ने भी इस ऐतिहासिक आयोजन की सराहना की। उन्होंने इसे युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। रूंगटा यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री संतोष रूंगटा ने विश्वविद्यालय की ओर से यह संकल्प दोहराया कि उनका संस्थान छत्तीसगढ़ को स्किल हब बनाने में राज्य सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा।

विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 न केवल एक आयोजन था, बल्कि यह एक प्रेरणा थी—एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने यह सिद्ध किया कि यदि नीति, नीयत और प्रयास सही हों तो युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी ताकत बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने यह स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह न केवल देश की आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, बल्कि ग्लोबल स्किल कैपिटल बनने की पूरी क्षमता रखता है।

दक्षिण भारतीय सेमिया उपमा...

जी.वी.एस.रुक्मणि देवी

वर्मिसेली उपमा एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय नाश्ता रेसिपी है जिसे सेवई, सब्ज़ियाँ, दाल, काजू और मसालों से बनाया जाता है। सेवई उपमा के नाम से भी जाना जाने वाला यह स्वस्थ, शाकाहारी और स्वादिष्ट नाश्ता है जिसे 20 मिनट में बनाया जा सकता है। वर्मिसेली उपमा को नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी, दही के साथ परोसें। सब्ज़ियों के साथ या बिना सब्ज़ियों के दो तरह से बनाया जाता है। मैंने यह पर ढेर सारी सब्जियां का उपयोग कर के या टेस्टी हेल्दी उपमा बनाया है।

सामग्री

1 कप सेवई
1 गाजर बारीक कटी हुई
1 प्याज बारीक कटी हुई
1 टमाटर बारीक कटी हुई
1 शिमला मिर्च कटी हुई
2 हरी मिर्च
1/4 कप हरी मटर
1 चम्मच घी
1 चम्मच तेल
नमक स्वादानुसार
2 चम्मच शेजवान चटनी
2 चम्मच टोमाटोसॉस
धनिया पत्ती आवश्यकतानुसार
1 चम्मच शेजवान फ्राइड राइस मसाला

बनाने की विधि

1 चम्मच घी गर्म करें और फिर इसमें वर्मिसेली को ही सुनहरा होने तक रोस्ट करें और फिर 2 कप पानी मिलाकर 5 मिनट तक पकाएं। और फिर छान कर अलग रखें। दूसरी तरफ एक कढ़ाई में तेल गरम करें और इसमें कटी हुई हरी मिर्च और प्याज़ मिलाकर भूनें और फिर इसमें गाजर और शिमला मिर्च मिलाएं और फिर इसमें हरी मटर मिलाएं सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर पकाएं 7 अब इसमें नमक और शेजवान फ्राइड राइस मसाला मिलाएं और फिर 2 मिनट ढक कर रख दें। अब इसमें टमाटर मिलाएं। अब इसमें उबाली हुई वर्मिसेली मिलाएं और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें अब इसमें शेजवान चटनी और टोमाटोसॉस मिलाएं और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसमें धनिया पत्ती मिलाकर गैस बंद कर दें। वर्मिसेली उपमा तैयार है इसे प्लेट में निकाल लें और गरमागरम सर्व करें।

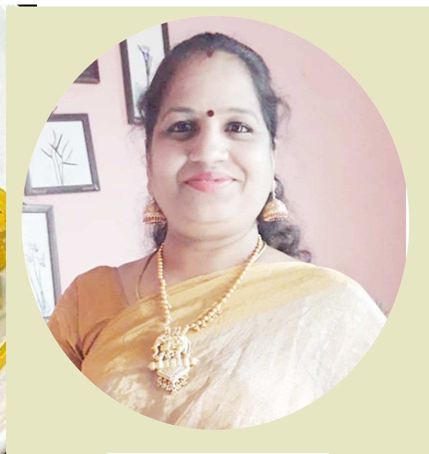

(जी.वी.एस.रुक्मणी देवी)

बरसात के मौसम में हम स्वस्थ कैसे रहें....?

राखी श्रीवास्तव

मानसून ताज़गी भरी राहत के अलावा, कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लेकर आता है। बारिश के बाद मिट्टी की ख़ुशबू सुकून तो देती है, लेकिन यह एक ऐसा मौसम भी है जो नमी को बढ़ता है और जलजनित बीमारियाँ होने लगती हैं। तो आप इस खूबसूरत मौसम का आनंद लेते हुए स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? यह व्यापक मार्गदर्शिका आपको मानसून के मौसम से जुड़ी कई हेल्थ टिप्स प्रदान करेगी, जो आपको अपने स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मौसम का आनंद लेने में मदद करेंगी।

साफ और उबला हुआ पानी पिएं

मानसून के दौरान, जल संसाधनों के दूषित होने का खतरा अधिक होता है, जिसके परिणामस्वरूप जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। हमेशा फ़िल्टर या उबला हुआ पानी ही चुनें, क्योंकि गर्मी से ज़्यादातर बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी मर जाते हैं। यात्रा करते समय, अपनी खुद की पानी की बोतल साथ रखें या सीलबंद और पैकेज्ड पानी ही पिएं।

अपने विटामिन C का सेवन बढ़ाएं

संतरे और नींबू जैसे विटामिन ष्ट से भरपूर फल खाने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी और संक्रमण से लड़ने में मदद मिलेगी।

प्रोबायोटिक का सेवन बढ़ाएं

अच्छी आंत का स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। दही जैसे प्रोबायोटिक्स का सेवन आंत में अच्छे बैक्टीरिया के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकता है। एक स्वस्थ आंत इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर बनाती है, जो मानसून के मौसम में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

हर्बल टी शामिल करें

हर्बल टी न केवल गले को शांत करने में मदद करती है बल्कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है और पाचन में सहायता करती है। अदरक की चाय, तुलसी की चाय या मसाला चाय मानसून के दौरान बेहतरीन विकल्प हैं। वे एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं जो आपके शरीर के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करते हैं।

कड़वे खाद्य पदार्थ खाएं

अपने आहार में करेला, नीम और मेथी जैसे कड़वे खाद्य पदार्थों को शामिल करने से न केवल पाचन में सुधार होता है बल्कि बारिश के मौसम में इम्यूनिटी को भी बढ़ावा मिलता है। इन खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रोगाणुरोधी गुण होते हैं जो शरीर को साफ करने और संक्रमणों को दूर रखने में मदद करते हैं। इन्हें अपने भोजन में शामिल करने से अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने और आम मौसमी बीमारियों को रोकने में मदद मिल सकती है।

जंक फूड से बचें

स्ट्रीट फूड से दूर रहना मानसून सेफ्टी टिप्स में से एक है। क्योंकि जंक फूड में दूषित पानी या कच्चे माल के इस्तेमाल की वजह से पेट खराब हो सकता है।

मसालेदार खाने से दूर रहें

मसालेदार खाना पेट में एसिड के स्राव को बढ़ाता है जिससे पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं। मानसून के मौसम में, मसालेदार खाने का सेवन कम करना बेहतर होता है क्योंकि इससे आपका पाचन थोड़ा कमज़ोर हो सकता है। यह मानसून के मौसम के लिए सबसे ज़रूरी हेल्थ टिप्स में से एक है।

मच्छरों के प्रजनन स्थानों को खत्म करें

स्थिर पानी मच्छरों के पनपने का स्थान है, जो डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियाँ फैला सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके घर के आस-पास कोई स्थिर पानी न हो। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए इन्सेक्ट रिपेलेंट और मच्छरदानी का उपयोग करें।

गंदे पानी में चलने से बचें

बरसात के मौसम में गंदे पानी में चलने से आपको कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं, इसलिए अगर ऐसा करना ज़रूरी हो, तो अपने पैरों को साफ पानी से जरूर धोएं और एंटीसेप्टिक लगाएँ।

नहाने के पानी में कीटाणुनाशक मिलाएं

बरसात के मौसम में, बढ़ी हुई नमी और रुका हुआ पानी बैक्टीरिया और फंगस के लिए प्रजनन स्तान बन सकता है। संक्रमण के जोखिम को कम करने और अच्छी स्वच्छता बनाए रखने के लिए, नहाने के पानी में एंटीसेप्टिक लिक्विड की कुछ बूँदें जैसे कीटाणुनाशक मिलाने की सलाह दी जाती है। यह त्वचा पर मौजूद सूक्ष्मजीवों को मारने, आपको स्वस्थ रखने और फंगल संक्रमण जैसी आम बरसाती बीमारियों को रोकने में मदद कर सकता है।

नम कपड़ों को आयरन करें

बरसात के मौसम में, कपड़े अक्सर उच्च आर्द्रता (ह्यूमिडिटी) के कारण पूरी तरह से सूख नहीं पाते हैं, जो बदले में फफूंद और अप्रिय गंध के विकास को बढ़ावा देता है। कपड़ों को आयरन करने से न केवल सिलवटों को मिटने में मदद मिलती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि वे पूरी तरह से सूखे और नमी रहित हैं। आयरन की गर्मी किसी भी बचे हुए बैक्टीरिया या फफूंद के बीजाणुओं को भी मार देती है।

कपड़े और जूते ठीक से सुखाएँ

-धोने के बाद, कपड़ों को अच्छी तरह हवादार जगह पर सूखने के लिए लटका दें या हो सके तो ड्रायर का इस्तेमाल करें। अपने जूतों से इनसोल निकालें और नमी को सोखने के लिए उनमें अख़बार भर दें। फिर उन्हें सूखी और हवादार जगह पर रखें। गीले कपड़े और जूते पहनने से बचें क्योंकि उनमें बैक्टीरिया और फफूंद हो सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

हाथ धोएं

मानसून के लिए दी गयी हेल्थ टिप्स में से एक है हाथों की अच्छी स्वच्छता बनाए रखना, क्योंकि यह अकेले ही मानसून की अधिकांश बीमारियों को रोकता है। अपने हाथों को कम से कम 20 सेकंड तक साबुन से स्क्रब करें और फिर उन्हें अच्छी तरह से धो लें। जब साबुन उपलब्ध न हो, तो कम से कम 60 प्रतिशत अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर एक आसान विकल्प हैं।

पर्याप्त नींद लें

बारिश के मौसम में पर्याप्त नींद लेना इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और आपके शरीर को संक्रमणों से लड़ने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है। स्वस्थ रहने और अपने ऊर्जा स्तर को उच्च रखने के लिए 7-9 घंटे की आरामदायक नींद लें ।अच्छी नींद मूड और सामान्य स्वास्थ्य को भी बेहतर बना सकती है, जिससे नमी और ठंड से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना आसान हो जाता है।

नियमित रूप से व्यायाम करें

नियमित शारीरिक गतिविधि इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और आपको स्वस्थ रखती है; लेकिन व्यायाम करते समय अच्छी स्वच्छता बनाए रखना भी महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप फिटनेस सेंटर में साझा उपकरण का उपयोग कर रहे हैं।

अंत में, जानकारी रखें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ और ऊर्जावान बने रहकर मानसून के मौसम का आनंद लें। याद रखें कि आपका स्वास्थ्य प्राथमिकता है, विकल्प नहीं - आइए सुनिश्चित करें कि इसे वह ध्यान मिले जिसका यह हकदार है।

राखी श्रीवास्तव

विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की दिशा में सार्थक पहल सहभागिता और संवेदनशीलता की ओर अग्रसर-पीएम जनमन योजना

छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों के समावेशी और सतत विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान (पीएम जनमन योजना) एक प्रभावशाली बदलाव का माध्यम बनकर उभर रही है। हाल ही में राज्य विधानसभा स्थित मुख्य समिति कक्ष में इस योजना के क्रियान्वयन की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य के आदिम जाति और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम ने की।

जनजातीय सम्मान और संस्कृति के अनुरूप विकास की दिशा

मंत्री श्री नेताम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि विकास कार्यों में सहभागिता और संवेदनशीलता अनिवार्य है। विशेष पिछड़ी जनजातियों की सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखते हुए उनके लिए ग्रामीण परिवेश में समृद्ध और सुविधायुक्त आवास निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जनजातियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुँचाना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है।

पीएम जनमन योजना- केवल अधोसंरचना नहीं, बल्कि समर्पित मिशन

श्री नेताम ने योजना को केवल सड़कों, पुलों और आवासों के निर्माण तक सीमित न मानते हुए इसे एक समर्पित मिशन बताया। उन्होंने कहा, यह अभियान अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने की भावना से प्रेरित है। सुशासन का सार तभी सार्थक होगा जब शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और बुनियादी सुविधाएँ वंचित वर्गों तक पहुँचें।

योजना की प्रगति- आँकड़ों में विकास की तस्वीर

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के पाँच विशेष पिछड़ी जनजातियों-अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और पहाड़ी कोरवा - के विकास के लिए 18 जिलों के 53 विकासखंडों की 1541 ग्राम पंचायतों में योजना लागू की गई है। इन समुदायों के लगभग 56,569 परिवारों में कुल जनसंख्या 2.12 लाख से अधिक है, जिनकी 2365 बसाहटें चिन्हित की गई हैं।

- आवास निर्माण- योजना के तहत 33,132 पीएम आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 9,901 पूर्ण हो चुके हैं। 14,000 से अधिक आवास निर्माणाधीन हैं, जिनके लिए तीसरी किश्त जारी हो चुकी है।
- सड़क संपर्क-वर्ष 2023-24 में 333 कार्यों की स्वीकृति दी गई, जिनमें 1170 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है। इनमें से 475 किलोमीटर पूर्ण हो चुकी है।
- आंगनबाड़ी केन्द्र- 191 केन्द्रों को स्वीकृति दी गई और संचालित किया जा रहा है।
- स्वास्थ्य सेवाएँ- 1442 बसाहटों में से 989 ग्राम स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा संतृप्त किए जा चुके हैं। 317 स्थानों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट कार्यरत हैं, शेष 26 पहुँचविहीन ग्रामों में बाइक मेडिकल यूनिट शुरू करने की योजना है।

शिक्षा, कनेक्टिविटी और रोजगार- एकीकृत विकास की ओर कदम

बैठक में विद्युत आपूर्ति, आश्रम-छात्रावासों का निर्माण, मोबाइल टावर की स्थापना, बहुउद्देशीय केन्द्रों तथा वन धन विकास केन्द्रों की स्थापना जैसे विषयों पर भी समीक्षा हुई। इसके साथ ही व्यावसायिक एवं कौशल आधारित शिक्षा की गति एवं गुणवत्ता को सुदृढ़ करने की रणनीति पर विचार किया गया।

समावेशी विकास की अवधारणा

राज्य सरकार का स्पष्ट रुख है कि 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' की भावना के साथ विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन स्तर को उन्नत किया जाए। श्री नेताम ने यह भी कहा कि योजना को जमीनी हकीकत से जोड़ते हुए ही वास्तविक परिवर्तन संभव है। योजना के प्रत्येक घटक को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सफलता की कसौटी है।

पीएम जनमन योजना छत्तीसगढ़ की विशेष पिछड़ी जनजातियों के जीवन में ठोस और दीर्घकालिक परिवर्तन लाने की दिशा में एक आश्वस्तिकारी पहल है। राज्य सरकार की यह नीति-जो सहभागिता, संवेदनशीलता और समर्पण पर आधारित ह-निश्चित रूप से सामाजिक न्याय और समग्र विकास का सशक्त उदाहरण बनेगी।

प्रदेश में खेती-किसानी का कार्य तेजी के साथ जारी

- राज्य में अब तक 36.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में विभिन्न फसलों की बोनी लक्ष्य का 75 प्रतिशत हुई बोनी
- इस खरीफ सीजन में 48.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का है लक्ष्य
- मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का निर्देश: किसानों को उनकी मांग के अनुरूप सुगमता से मिले खाद-बीज
- किसानों को 10.20 लाख मीट्रिक टन खाद और 7.22 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरित

प्रदेश में खेती-किसानी का काम तेजी के साथ जारी है। राज्य में अब तक 36.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में धान, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, मूंग, मूंगफली, रामतिल सहित विभिन्न फसलों की बोनी हो चुकी है, जो लक्ष्य का 75 प्रतिशत है। इस खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 48.85 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बोनी का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने किसानों को खेती-किसानी में सहुलियतें प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक सहयोग करने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। उन्होंने किसानों को उनकी मांग के अनुसार सुगमता के साथ प्रमाणित खाद-बीज का वितरण करने को भी कहा हैं। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा इन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है। प्रदेश के किसानों को अब तक 10.20 लाख मीट्रिक टन खाद और 7.22 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया जा चुका है। 21 जुलाई 2025 की स्थिति में प्रदेश में अब तक 446.1 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई है, जबकि प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 1238.7 मिमी है।

कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष खरीफ 2025 के लिए प्रदेश में 4.95 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें समस्त स्त्रोतों से 7.88 लाख क्विंटल बीज का भंडारण कर अब तक 7.22 लाख क्विंटल बीज का वितरण किसानों को किया गया है, जो मांग का 146 प्रतिशत है। जबकि खरीफ वर्ष 2024 में राज्य में बीज निगम से 4.64 लाख क्विंटल प्रमाणित बीज का वितरण किया गया था। इसी प्रकार प्रदेश में इस खरीफ सीजन में 14.62 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध 13.78 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में भंडारण किया गया है। उक्त भंडारण के विरूद्ध 10.20 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो लक्ष्य का 70 प्रतिशत है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि खाद-बीज वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पर कड़ी कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सोसायटियों में पर्याप्त खाद-बीज का भण्डारण कर सतत निगरानी करने को कहा गया है।

BPT कर रहे स्टूडेंट्स के लिए करियर विकल्प...

सुरेश प्रजापति (बिजनौर) पूछते हैं कि उनका बेटा देहरादून के सुभारती मेडिकल कॉलेज से BPT कर रहा है। वह BPT के साथ या बाद में कौन-से कोर्स कर सकता है? सीनियर करियर काउंसलर श्वेता खन्ना भंद्राल बताती हैं कि BPT के साथ या उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट और डिग्री कोर्स करके करियर को विस्तार दिया जा सकता है।

BPT के साथ या बाद में किए जा सकने वाले कोर्स

1. योगा / योगिक साइंस (Yogic Science)

- सर्टिफिकेट और डिप्लोमा दोनों कोर्स उपलब्ध
- रिहैबिलिटेशन और मानसिक स्वास्थ्य में उपयोगी

2. न्यूरोथेरेपी

- ब्रेन, नर्वस सिस्टम संबंधित रोगों की थेरेपी
- निजी प्रैक्टिस के लिए उपयोगी

3. स्ट्रेन्थ एंड कंडीशनिंग

- एथलीट्स और फिटनेस ट्रेनिंग से जुड़ा कोर्स
- स्पोर्ट्स सेक्टर में नौकरी के अवसर

4. Certified MDT (Mechanical Diagnosis & Therapy)

- अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त तकनीक
- रीढ़ की हड्डी और मस्कुलर दर्द के इलाज में उपयोगी

5. वुमन हेल्थ फिजियोथेरेपी

- महिलाओं से जुड़े स्वास्थ्य मुद्दों पर केंद्रित
- मेटरनिटी क्लीनिक, हॉस्पिटल और हल्थ सेक्टर में डिमांड

6. स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी

- खिलाड़ियों की चोटों और फिटनेस पर काम
- स्पोर्ट्स टीम्स और क्लब्स में करियर की संभावना

डिग्री या कोर्स कहां से करें

- IGNOU, SVYASA, Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, NITTE, और अन्य मेडिकल यूनिवर्सिटीज से ये कोर्स उपलब्ध हैं।

MSc केमिस्ट्री के बाद करियर के विकल्प

अमन कनौजिया पूछते हैं कि उन्होंने 2025 में MSc केमिस्ट्री पूरी की है और अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए कौन-से विकल्प मौजूद हैं? सीनियर करियर काउंसलर रत्ना पंथ बताती हैं कि MSc केमिस्ट्री के बाद स्टूडेंट्स के पास तीन प्रमुख रास्ते होते हैं:-

1. शैक्षणिक / रिसर्च करियर

- GC NET/JRF: क्वालीफाई करने पर लेक्चररशिप और रिसर्च फेलोशिप
- PhD: रिसर्च के लिए
- B.Ed + TET/CTET: स्कूल टीचिंग में करियर

2. इंडस्ट्री-फोकस्ड कोर्स

इन कोर्सेस से आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फार्मा, और क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं:-

- इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री
- फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री
- एनालिटिकल केमिस्ट्री

- क्वालिटी कंट्रोल / क्वालिटी एश्योरेंस

कंपनियां

- ONGC, GAIL, DRDO, GAT, BIAS

3. जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेशन कोर्सेस

- Lab Safety & Hazard Management
- Green Chemistry
- Environmental Sustainability
- AYUSH Certification Training

इन कोर्सेस के बाद आप पर्यावरणीय संगठन, रिसर्च लैब्स या फार्मा कंपनियों में काम कर सकते हैं।

व्यक्तिगत व्यवसाय की संभावना

MSc केमिस्ट्री और BPT, दोनों ही क्षेत्रों में आप चाहें तो फ्रीलांसिंग या स्वतंत्र क्लिनिक / लैब खोलकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। सरकार की Startup India, MSME जैसी योजनाएं इसमें मदद कर सकती हैं।

- BPT स्टूडेंट्स को क्लिनिकल और वेलनेस दोनों क्षेत्रों में अवसर मिलते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स उनके स्किल को बढ़ा सकते हैं।
- MSc केमिस्ट्री के छात्र चाहें तो रिसर्च, इंडस्ट्री या टीचिंग–तीनों में अपने लिए रास्ता बना सकते हैं।

सुबह खाली पेट बच्चों को दूध पिलाने की गलती न करें जानिए इसके नुकसान और सही समय

हर माता-पिता की यह स्वाभाविक इच्छा होती है कि उनके बच्चे स्वस्थ, ऊर्जावान और मानसिक रूप से सक्षम बनें। इसके लिए वे बच्चों के आहार में पौष्टिक चीज़ें शामिल करते हैं और दूध को सबसे पहला पोषक विकल्प मानते हैं। यह मान्यता काफी हद तक सही भी है क्योंकि दूध में कैल्शियम, प्रोटीन और अन्य जरूरी पोषक तत्व होते हैं, जो बच्चों के शारीरिक विकास और हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दूध पिलाने का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि दूध पिलाना? विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह खाली पेट बच्चों को दूध पिलाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आइए जानते हैं क्यों ऐसा कहा जाता है और दूध कब और कैसे देना सबसे सही होता है।

सुबह खाली पेट दूध क्यों नहीं देना चाहिए?

1. पाचन तंत्र पर असर

दूध में फाइबर और पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। जब बच्चा सुबह उठकर खाली पेट दूध पीता है, तो यह पेट को पर्याप्त ऊर्जा नहीं देता और पाचन क्रिया को सुस्त बना सकता है। इससे बच्चों को दिनभर थकान, सुस्ती और चिड़चिड़ापन महसूस हो सकता है।

2. भूख न लगना

दूध में वसा और प्रोटीन होते हैं जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं। अगर बच्चा सुबह दूध पी लेता है, तो उसे जल्दी भूख नहीं लगती और वह नाश्ता नहीं करता। इससे अन्य जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, जो विकास को प्रभावित करती है।

3. गैस, सूजन और एसिडिटी

दूध में फाइबर की कमी के कारण यह कुछ बच्चों में गैस, पेट में सूजन और एसिडिटी जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है। खासकर जिन बच्चों का पाचन कमजोर होता है, उनके लिए सुबह खाली पेट दूध पचाना मुश्किल हो सकता है।

रात को दूध देने से भी हो सकते हैं नुकसान

आयरन का अवशोषण रुकता है

रात को अधिक मात्रा में दूध पीने से बच्चों के शरीर में आयरन का अवशोषण बाधित होता है। यह एनीमिया जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है।

ब्लड शुगर का स्तर बढ़ सकता है

दूध में नैचुरल शुगर की मात्रा होती है, जो रात को सेवन करने पर ब्लड शुगर लेवल को असंतुलित कर सकती है।

बच्चों को दूध कब और कैसे दें?

विशेषज्ञों की सलाह है कि बच्चों को दूध कभी भी खाली पेट नहीं देना चाहिए। इसके बजायः

- सुबह पहले हल्का नाश्ता दें ड्ड जैसे फल (सेब, केला, पपीता), या भारतीय नाश्ते जैसे इडली, डोसा, उपमा, पोहा।
- नाश्ते के 30-45 मिनट बाद दूध दें।
- शाम के स्नैक्स के बाद भी दूध देना एक अच्छा विकल्प हो सकता है।
- दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स पाउडर या ओट्स मिलाकर भी दिया जा सकता है।

बेहतर विकल्प क्या हो सकते हैं?

दूध की जगह या दूध से पहले बच्चों को ये चीजें दी जा सकती हैंः

दूध अपने आप में एक संपूर्ण आहार माना जाता है, लेकिन इसका सेवन सही समय पर और सही तरीके से किया जाए तो ही इसका अधिकतम लाभ मिलता है। बच्चों को सुबह उठते ही दूध देना एक आम आदत हो सकती है, लेकिन यह आदत उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन सकती है। इसलिए माता-पिता को चाहिए कि वे बच्चों को पहले हल्का नाश्ता दें और फिर दूध पिलाएं। इससे न केवल उनका पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, बल्कि वे पूरे दिन ऊर्जावान और स्वस्थ रहेंगे।

विकल्प	फायदे
फल जैसे केला, सेब, पपीता	फाइबर और विटामिन से भरपूर
पोहा, उपमा, इडली	कार्बोहाइड्रेट और आयरन युक्त
ओट्स, बाजरे का दलिया	पचाने में आसान, एनर्जी से भरपूर

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के ऐतिहासिक निर्णय- राजधानी क्षेत्र विकास, वंचित समुदायों का सशक्तिकरण और स्टार्टअप नीति को मिली हरी झंडी...

छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए राजधानी क्षेत्र के समेकित विकास, वंचित वर्गों के सशक्तिकरण और युवाओं के स्टार्टअप सपनों को उड़ान देने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक दूरगामी महत्व के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

1. छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना को मंजूरी

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) की तर्ज पर अब छत्तीसगढ़ में भी राजधानी क्षेत्र (State Capital Region - SCR) का विकास सुनिश्चित करने हेतु एक सशक्त प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर अटल नगर को शामिल करते हुए SCR की परिकल्पना की गई है।
- तेजी से बढ़ती शहरी आबादी और 2031 तक संभावित 50 लाख की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सुव्यवस्थित और पर्यावरण-संवेदनशील विकास की योजना।

- **प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र**
  - क्षेत्रीय विकास की व्यापक योजना बनाना।
  - सार्वजनिक और निजी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना।
  - निवेश को बढ़ावा देना।
  - शहरी विस्तार को नियंत्रित और नियोजित करना।

इस निर्णय से राजधानी क्षेत्र में बेहतर आधारभूत संरचना, परिवहन, जल आपूर्ति, आवास और पर्यावरण संतुलन सुनिश्चित करने की दिशा में एक नया अध्याय शुरू होगा।

2. पैनआईआईटी फाउंडेशन के साथ साझेदारी- वंचितों के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी

सरकार ने एक दूरदर्शी पहल करते हुए पैनआईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (PanIIT) के साथ मिलकर एक गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन को भी मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य राज्य के आदिवासी युवाओं, महिलाओं और तृतीय लिंग समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है।

उद्देश्य

- संस्थागत व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास।
- ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देना।
- रोजगारपरक प्रशिक्षण के जरिए आयवृद्धि।

पैनआईआईटी फाउंडेशन - IIT के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित यह संगठन राष्ट्र निर्माण मिशन के तहत विभिन्न राज्यों में आजीविका और उद्यमिता से जुड़े कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। छत्तीसगढ़ में यह पहल हाशिए पर खड़े समुदायों के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी।

3. स्टार्टअप और नवाचार नीति 2025 को मंजूरी

राज्य सरकार ने युवा सशक्तिकरण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ÷छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति÷ लागू करने का निर्णय लिया है। यह नीति विशेषकर तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों को नवाचार के लिए प्रेरित करेगी।

प्रमुख लक्ष्य

- 100 तकनीकी संस्थानों तक पहुंच बनाना।
- 50,000 विद्यार्थियों को इस पहल से जोड़ना।
- 500 प्रोटोटाइप्स का निर्माण और समर्थन।
- 500 बौद्धिक संपदा अधिकार (IPRs) की फाइलिंग।
- 150 स्टार्टअप्स की स्थापना को बढ़ावा देना।

मुख्य फोकस क्षेत्र

- जनजातीय क्षेत्रों में नवाचार केंद्रों की स्थापना।
- कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य और विनिर्माण जैसे प्राथमिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान।

यह नीति युवाओं में नई सोच, शोध और तकनीक आधारित उद्यमिता की नींव रखेगी और राज्य को नवाचार का केंद्र बनाने में सहायक होगी।

4. छोटे व्यापारियों को राहत- बकाया कर निपटान विधेयक को मंजूरी

राज्य सरकार ने व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान (संशोधन) विधेयक, 2025 के प्रारूप को भी स्वीकृति दी है।

मुख्य लाभ

- व्यापारियों पर लदे पुराने कर, जुर्माने और ब्याज को समझौते के माध्यम से समाप्त किया जाएगा।
- कर न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित

होगा।

- एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) इकाइयों को गति मिलेगी और कारोबार में सुगमता आएगी।

यह पहल राज्य के आर्थिक पारिस्थितिकी को सशक्त बनाने और कारोबार में विश्वास बहाली की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है।

छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद के ये निर्णय राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति देने वाले हैं। एक ओर जहां राजधानी क्षेत्र के लिए नियोजित विकास की नींव रखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर वंचित समुदायों और युवाओं को सशक्त बनाने की ठोस पहल हो रही है।

इन नीतिगत कदमों से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार राज्य को ÷विकसित, समावेशी और नवाचारी छत्तीसगढ़÷ के रूप में आकार देने की दिशा में गंभीरतापूर्वक अग्रसर है।

कोडिंग' की दाल में 'केयरिंग' का तड़का नौकरी की सही रेसिपी है

एन. रघुरामन का कॉलम

वह पोस्ट ग्रेजुएट है। उसने कई इंटर्नशिप भी की। फिर एक राजनेता के ऑफिस में काम किया, जहां वो उनके मतदाताओं से मिलती। वो स्मार्ट है। संचार में और वहां आने वाले लोगों को संभालने में कुशल है। चूंकि वो आम महिला-पुरुषों को अधिकारीगण आदि से मिलाने में मदद करती थीं, जिनके निर्णयों से जनता को लाभ होता है।

ऐसे में उसने किसी व्यक्ति की समस्या को समाधान प्रदाता से मिलाने की कुशलता विकसित कर ली। लेकिन उसकी एक ही समस्या थी। राजनेताओं के कामकाज का कोई समय नहीं होता। रोजाना लंबे समय तक काम करने से उसके बच्चे पर असर पड़ रहा था। इसीलिए उसने नौकरी बदलने का निर्णय किया। पिछली जनवरी में उसने एक बड़े अस्पताल में काम करने वाले मेरे एक परिचित से संपर्क किया, ताकि वह वहां नौकरी के लिए उनकी सिफारिश कर सके। और उसे नौकरी मिल गई।

जाहिर तौर पर वह इसलिए चुनी गई, क्योंकि उसमें शिकायत करने वाले मरीजों को संभालने की क्षमता थी और जॉइन करने के पहले दिन से ही वह उन्हें शांत रखने लग गई। 6 महीने का प्रोबेशन पूरे करने से पहले, महज एक महीने में ही उसने स्थायी नौकरी की मांग कर दी। और उसे वह भी मिल गई। उसका ख्याल मुझे तब आया जब मैं इस हफ्ते जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा पढ़ रहा था। इसमें बताया गया कि 15 से 29 साल के शहरी युवाओं में बेरोजगारी दर एक महीने में एक प्रतिशत बढ़ गई है। जून में ये 18.8त्न हो गई। कहीं ना कहीं यह दो बातों की ओर संकेत करती है। 1. अकेली शिक्षा अब रोजगार-स्थायित्व की गारंटी नहीं। 2. नियोक्ता चाहते हैं कि आप जॉइन करने के पहले दिन से ही रिजल्ट देने लगें। मुंबई में कुशल व शिक्षित युवाओं की एक पीढ़ी अभी भी बेरोजगार है।

जी हां, ये वही शहर है, जहां गर्व से कहते थे कि 'मुंबई में कोई भूखा नहीं सोता।' लेकिन आज यह बात सच नहीं है। मुम्बई ऐसा अकेला शहर नहीं है। अमेरिका से लेकर यूके तक दुनियाभर में कॉलेज ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं के बीच बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

अमेरिका के भी ऐसे मासिक बेरोजगारी डेटा की पड़ताल करें तो पता चलता है कि अमेरिकी पुरुषों में भी बेरोजगारी तेजी से बढ़ी है। यह पांच प्रतिशत से कम थी, जो अब 7त्न से अधिक हो गई है। जबकि महिलाओं में बेरोजगारी घटी है। इस दावे का समर्थन करने वाले एक डेटा से पता चलता है कि पिछले एक वर्ष में युवा महिला ग्रेजुएट्स द्वारा भरी गई 1.35 लाख नौकरियों में से 50 हजार नौकरियां अमेरिका के हेल्थ केयर सेक्टर में थीं।

स्पष्ट रूप से इसका कारण उम्रदराज आबादी की बढ़ती मांग के साथ ऑटोमेशन, घरों में एआई संचालित उपकरणों का प्रवेश और रोजमर्रा की चिकित्सा जरूरतें हैं। ये सब बताता है कि एआई मौजूदा व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कारक है।

इसका जवाब सही भी है और गलत भी। सही इसलिए, क्योंकि यह उतनी नौकरियां पैदा नहीं कर रहा, जितनी पुरानी नौकरियां खत्म कर रहा है। गलत इसलिए, क्योंकि एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पदों पर भर्तियों में फिर उछाल देखा जा रहा है। इसलिए तकरीबन 30 वर्ष की उम्र के लोग, जो कम से कम 60 हजार रु. प्रतिमाह वाली नौकरी खोज रहे हैं, उन्हें उस स्थान की जनसांख्यिकी भी पढ़नी चाहिए, जहां नौकरी ढूंढ रहे हैं। और उन्हें कोडिंग से 'केयरिंग' की ओर रुख करना चाहिए। मुंबईकरों में नया नारा है, 'कोडिंग सीखने के साथ-साथ केयरिंग भी सीखो।'

ऐसा इसलिए क्योंकि एक शहर के तौर पर मुंबई भी बूढ़ा हो रहा है। और उस आबादी को देखभाल चाहिए। यही कारण है कि शुरुआत में जिस लड़की का जिक्र मैंने किया, उसे हेल्थ सेक्टर में जल्दी नौकरी मिल गई। और वह पहले दिन से ही अपने नियोक्ता के लिए समस्याओं का समाधान करने वाली बन गई।

फंडा यह है कि जैसे पैसा कंपनी के प्रदर्शन के पीछे भागता है, मेरा मतलब निवेशक निवेश से पहले कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं, वैसे ही आपका प्रदर्शन करियर को आगे बढ़ाता है। हेल्थकेयर जैसा क्षेत्र चुनें, जो अभी फल-फूल रहा है। और यदि कोडिंग में 'केयरिंग' का तड़का लगा सकते हैं तो फिर देखिए कैसे आपकी 'रेसिपी' जायकेदार बन जाएगी। मेरा मतलब है आपकी सैलरी!

सैयारा- एक तन्हा तारा जिसने रोशन कर दिया पूरा बॉक्स ऑफिस

सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वह भावना भी होता है – कुछ महसूस कराने वाला, कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला। इसी भावना को साकार किया है निर्देशक मोहित सूरी की नई फिल्म 'सैयारा' ने। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी यह फिल्म आजकल हर सिनेप्रेमी की जुबां पर है। इसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है, बल्कि लोगों के दिलों में भी खास जगह बना ली है।

3 दिनों में 83 करोड़!

फिल्म 'सैयारा' ने महज तीन दिनों में 83 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर ली है, जो आज के दौर में किसी भी नई जोड़ी की फिल्म के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

- पहले दिन- 21 करोड़
- दूसरे दिन- 25 करोड़
- तीसरे दिन- 37 करोड़

इस रफ्तार को देखकर साफ कहा जा सकता है कि फिल्म जल्द ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर लेगी।

इसके साथ ही सैयारा इस साल की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्मों में शुमार हो चुकी है। यह फिल्म अनुपम खेर की तन्वी द ग्रेट और सोनाक्षी सिन्हा की निकिता रॉय से टकराई, लेकिन दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए दर्शकों का दिल जीतने में सफल रही।

सैयारा- एक अनोखा नाम, एक गहरा मतलब

जब कोई फिल्म हिट होती है तो उसके हर पहलू पर बात होती है — कहानी, निर्देशन, संगीत और हां, टाइटल भी। 'सैयारा' नाम ने भी दर्शकों के बीच खासा ध्यान खींचा है।

सैयारा एक उर्दू और अरबी भाषा का शब्द है।

- उर्दू में इसका अर्थ होता है — आकाश में घूमने वाला खगोलीय पिंड यानी ग्रह या तारा।
- अरबी में इसे कहा जाता है — घूमता हुआ, निरंतर गतिशील।
- वहीं काव्य और शायरी की दुनिया में 'सैयारा' एक तन्हा और अकेले चमकते तारे के रूप में देखा जाता है — ऐसा तारा जो खुद जलकर औरों को रोशनी देता है।

फिल्म में भी है इस शब्द का विशेष स्थान

फिल्म के ट्रेलर में एक सीन है, जिसमें अभिनेत्री अनीत पड्डा, अभिनेता अहान पांडे को इस शब्द का गहरा मतलब समझाते हुए कहती हैं —

सैयारा का मतलब, तारों में एक तन्हा तारा।
जो खुद को रोशन करके कर दे जग ये सारा।
तुम हो न मेरे सैयारा।

यही संवाद फिल्म के इमोशनल और फिलॉसॉफिकल बैकबोन की

तरह काम करता है। 'सैयारा' सिर्फ एक नाम नहीं, एक भावना है — आत्मबल, अकेलेपन की ताकत और प्रेम की चमक।

अभिनय और निर्देशन की तारीफ

अहान पांडे और अनीत पड्डा — दोनों का यह डेब्यू है, लेकिन दर्शकों और समीक्षकों ने उनके अभिनय को सराहा है। अहान का गंभीर और संवेदनशील किरदार दर्शकों के दिल को छू जाता है, तो अनीत की मासूम लेकिन मजबूत उपस्थिति स्क्रीन को जीवंत कर देती है।

निर्देशक मोहित सूरी, जो पहले भी आशिकी 2 और एक विलेन जैसी हिट और भावनात्मक फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, ने एक बार फिर अपने निर्देशन से साबित कर दिया कि इमोशनल कहानियों को पर्दे पर गहराई से उतारने में उनका कोई जवाब नहीं।

संगीत और संवाद- दिल छू लेने वाले

फिल्म का संगीत भी इसकी सफलता में एक अहम भूमिका निभा रहा है। रोमांटिक गानों से लेकर सूफियाना टच तक, हर गीत कहानी को आगे बढ़ाता है और दर्शकों की भावना को छूता है।

तन्हा तारा, तू ही मेरा सैयारा, और चुप चुप के रातों में जैसे गाने पहले ही सोशल मीडिया और म्यूजिक चार्ट्स पर ट्रेंड कर रहे हैं।

फिल्म के संवाद भी युवाओं को काफी प्रभावित कर रहे हैं, खासकर वे जो आत्म-संघर्ष और खुद को खोजने की यात्रा में हैं।

युवाओं में दीवानगी

फिल्म खासतौर पर युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय हो रही है। सोशल मीडिया पर #Sayyara और #YouAreMySayyara जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं। कॉलेज स्टूडेंट्स, कपल्स, और फिल्मी शायरी के शौकीनों में इसके डायलॉग्स और गीत वायरल हो चुके हैं।

रविवार को फिल्म की हिंदी ऑक्यूपेंसी लगभग 71.18% रही — जो साबित करती है कि दर्शक इसे बार-बार देखने जा रहे हैं।

22 रन की हार दिल तोड़ने वाली थी... लॉर्ड्स टेस्ट को याद कर इमोशनल हो गए मोहम्मद सिराज

मोहम्मद सिराज ने लॉर्ड्स टेस्ट में 22 रनों से मिली हार पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि यह दिल तोड़ने वाला था, क्योंकि टीम इंडिया जीत के करीब थी। उन्होंने रविंद्र जडेजा के संघर्ष की सराहना की। भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए तीसरे टेस्ट में सिर्फ 22 रन से हार का सामना करना पड़ा था। टीम इंडिया लॉर्ड्स टेस्ट जीतने के काफी करीब आ गई थी। इंग्लैंड ने भारत को 193 रन का टारगेट दिया था। उसके बाद भारत के 7 विकेट सिर्फ 82 रन पर गिर गए थे। इसके बाद भारत के निचले बल्लेबाजी क्रम ने रविंद्र जडेजा का साथ देने की पूरी कोशिश की। खासकर, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने। दोनों मिलकर कुल 84 बॉल फेस की थी।

भारतीय टीम संघर्ष करते-करते 170 रन तक पहुंच गई थी। लेकिन, इसके बाद सिराज ने एक बॉल पर डिफेंस किया, जो टप्पा खाकर उनके स्टंप्स में घुस गई। इसके बाद सिराज टूट के बिखर गए थे। वह मैदान पर ही बैठ गए थे। वहीं अब मैनचेस्टर में होने वाले चौथे टेस्ट से पहले सिराज ने लॉर्ड्स में मिली इस हार पर बयान दिया है।

22 रन की हार दिल तोड़ने वाली थी...

मोहम्मद सिराज ने मैनचेस्टर टेस्ट से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने 2021 में भी आखिरी विकेट लिया था। मैं बहुत भावुक इंसान हूं। स्कोर 2-1 हो सकता था। जड्डू भाई ने बहुत संघर्ष किया। लेकिन फिर मैंने खुद से कहा कि सीरीज अभी खत्म नहीं हुई है और मैं अपनी बल्लेबाजी पर काम करूंगा। हमने ऑस्ट्रेलिया के बाद से अपनी बल्लेबाजी पर कड़ी मेहनत करना जारी रखा। 22 रन की हार दिल तोड़ने वाली थी।

23 जुलाई से शुरू होगा मैनचेस्टर टेस्ट

23 जुलाई यानी बुधवार को मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड में भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है। बता दें कि मोहम्मद सिराज भारत और इंग्लैंड के बीच चल रही इस टेस्ट सीरीज में हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। उन्होंने अब तक 3 टेस्ट में 13 विकेट लिए हैं। सिराज ने कुल 654 गेंद अब तक इस सीरीज में फेंकी हैं।

जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
MINISTRY OF JAL SHAKTI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES,
RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Save water
करें वर्षा जल संरक्षित ज़रूर,
जल की कमी भी होगी दूर।
वर्षा जल
संरक्षित
घर
जल पुन: उपयोग
प्रणाली

छत्तीसगढ़ संवाद आर.ओ.-13342/51

बदलते बस्तर की नई तस्वीर

327 गांवों में
नियद नेल्ला नार योजना से तीव्र विकास

350 स्कूलों
में दोबारा शुरू हुई पढ़ाई

278 किलोमीटर
नई सड़कों का निर्माण

11 वृहद
पुलों का निर्माण

140 किलोमीटर
नई रेल लाइन विस्तार की स्वीकृति

1000 नए
मोबाइल टावरों की स्थापना

5,500 से
अधिक घरों का विद्युतीकरण

40,000 से
अधिक युवाओं को मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत रोजगार अवसर

3202 नए
बस्तर फाइटर्स के पदों का सृजन

5,500 प्रति
मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता का भुगतान

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

QR स्कैन करें

सुशासन से समृद्धि की ओर

Visit us : ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in छत्तीसगढ़ जनसंपर्क